



लड़ाकू विमान
तेजस में उड़ान
भरेंगे रक्षामंत्री

>> 3

दैनिक जागरण

सरोकार

शहर को साफ करने के

अभियान में जुटे पेशेवर

लुधियाना : पंजाब के लुधियाना शहर के

कुछ पेशेवर शहर की साफ-सफाई के महा

अभियान में जुटे

हैं। ये लोग रविवार

सुबह शहर के एक

करते हैं व सफाई

में जुट जाते हैं। यह युवा खुद सफाई करने

में स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को भी

साथ जोड़ लेते हैं।

(पेज-10)

जागरण विशेष

इस पत्थर की लचक को देख

कर खड़ भी लजा जाए

धनबाद : धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ

माइंस (आइआइटि) के म्यूजियम में एक

ऐसा पत्थर का

टुकड़ा मौजूद है,

जिसकी लचक

देखकर खड़ भी

लजा जाए। इतना ही नहीं, इस पत्थर की उम्र

जानकर भी चौंक जाएंगे आप। इस पत्थर

की उम्र 1.75 करोड़ वर्ष है।

(पेज-16)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

एनजीओ भी आरटीआइ एक्ट

के दायरे से बाहर नहीं : कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को

एक अहम फैसले में कहा कि सरकार से पैसे

लेने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)

सुचना के अधिकार कानून (आरटीआइ

एक्ट) के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या

अस्पताल, जो सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती

दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष मदद लेने

वाले संस्थान भी आरटीआइ के दायरे में

आते हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

कश्मीर में बिना वेंरीफिकेशन

आयुष्मान योजना का लाभ

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट

और मोबाइल सेवा बंद होने के बाद भी लोगों

को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कोई दिक्कत

नहीं हो रही है। गरीबों को आयुष्मान भारत

के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही

है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

ने विशेष छूट दे रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य

प्राधिकरण के सीईओ इंदु भूषण के अनुसार

कश्मीर में मरीजों का इलाज बिना ऑनलाइन

वेंरीफिकेशन के ही किया जा रहा है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

होटल व आउटडोर कैटरिंग पर

जीएसटी घटाने की तैयारी

नई दिल्ली : विदेशी और घरेलू पर्यटकों को

बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल होटलों

पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर

को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल

की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक

टैक्स वाले होटल कमरे पर जीएसटी की

दर 28 परसेंट से घटकर 18 परसेंट की जा

सकती है। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर

भी जीएसटी की दर 18 परसेंट से घटकर पांच

परसेंट की जा सकती है।

<

चुनावी इंतजाम पूरे, कल बज सकता है बिगुल

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग तैयार है। तमाम इंतजामों को कसौटी पर परख़ा जा चुका। उच्च पदस्थ सूत्रों के

अनुसार गुरुवार को आयोग चुनाव शेड्यूल की घोषणा कर सकता है। इसके

साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रदेश में करीब एक करोड़ 83 लाख मतदाता हैं। इस बार 98 लाख 33 लाख 323 पुरुष और 84 लाख 65 हजार 152 महिलाएं लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालेंगे।

मतपेटी की जगह ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) ने ले ली। पचीं पर मुहर लगाने की बजाय बटन दबाने का चलन शुरू हो गया। तकनीक के बूते मतदान प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है, लेकिन सौ फीसद मतदान का लक्ष्य अभी भी अचूक है। हालांकि अधिकतम वोटिंग के लिए आयोग के प्रयास रंग लाए जब वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में मतदान फीसद 76.13 पहुंच गया। इसके साथ ही हरियाणा गठन के बाद पहले विधानसभा

पिछले विधानसभा चुनावों में वने 76.13 फीसद मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना चुनौती

निर्वाचन विभाग की टीमों ग्रामीणों को समझा रही वोट की ताकत, पढ़े-लिखों पर फोकस



चुनाव में मतदान का रिकार्ड टूट गया। पांच दशक पहले हुए चुनावों में तब 72.65 फीसद लोगों ने वोट डाले थे।

हरियाणा 1967 से 2019 तक पहुंचते-पहुंचते कई पड़ाव पार कर चुका है। साक्षर होने से लेकर हर मायने में जनता जागरूक हुई है, लेकिन चुनाव का मत फीसद बढ़ाने में आयोग के पसोने छूट गए। केंद्रीय चुनाव आयोग और हरियाणा निर्वाचन विभाग भी इसे लेकर पशोपेस में हैं, कि आखिर क्यों लाख कोशिशों के बावजूद सौ प्रतिशत मतदान आज भी सपना है। केंद्रीय चुनाव आयोग व राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक

करने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ियों व कलाकारों तक का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सौ फीसद मतदान के जादुई आंकड़े के पास पहुंचना तो दूर, मुश्किल से 75 का आंकड़ा पार कर सका है।

निर्वाचन विभाग ने हालांकि अब अपनी रणनीति बदली है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को वोट की ताकत समझाने के साथ ही पढ़े-लिखे वर्ग पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। अब देखना यह है कि अगले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत पुराने सारे रिकार्ड तोड़ देता है या फिर मायूसी ही हाथ लगती है।

वर्ष	कुल मतदाता	मतदान प्रतिशत
1967	43,87,980	72.65
1968	45,52,539	57.26
1972	50,91,082	70.46
1977	59,38,821	64.46
1982	71,52,281	69.87
1987	87,00,628	71.24
1991	97,31,912	65.86
1996	1,11,55,242	70.54
2000	1,11,53,183	69.01
2004	1,27,35,888	71.96
2009	1,31,16,965	72.29
2014	1,63,03,742	76.13
(नोट : आंकड़े निर्वाचन विभाग के अनुसार)		

राष्ट्रभक्त युवा देने के लिए

महंत दिग्विजयनाथ ने रखी

कई विद्यालयों की नींव : योगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार को ब्रह्मालीन महंत दिग्विजयनाथ की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रधर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। संत होते हुए महंत दिग्विजयनाथ का स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना इस बात का प्रमाण है। आजाद भारत को राष्ट्रभक्त युवा देने के लिए उन्होंने 1932 में ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और कई विद्यालयों की नींव रखी। अपने दो महाविद्यालयों की संपति दान कर दिग्विजयनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

योगी ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ आनंदमठ की संन्यासी परंपरा के संत थे। समूची गोरखपीठ ने ही संन्यासी परंपरा का अनुसरण किया और मानती रही कि राष्ट्रधर्म ही हमारा व्यक्तिगत धर्म है। पीठ की हमेशा से मान्यता रही कि राष्ट्र की रक्षा संन्यासी का पहला कर्तव्य है। राष्ट्र का विकास व्यक्ति के विकास की आवश्यक शर्त है। उन्होंने कहा कि बाबा गंभीर नाथ की तपस्या में पले-बढ़े दिग्विजयनाथ हिंदुत्व के मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति की यह गर चले।

राष्ट्र निर्माण में महंत दिग्विजयनाथ के योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल संबंध के लिए नेहरू सरकार को कई बार महंत दिग्विजयनाथ की सहायता लेनी पड़ी थी। खिलाफत आंदोलन के बाद कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में दिग्विजयनाथ ने राष्ट्रवादी राजनीति का शिखनाक किया था। वाणपसी के विद्वान्नाथ मंदिर का द्वार सबके लिए खुलवावा।

अदालत का राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इन्कार

जागरण ब्यूरो, कोलकाता

कोलकाता की जिला सत्र अदालत ने मंगलवार को शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। कुमार को सीबीआइ ने करोड़ों रुपये के सारथा चिटफंड घोटाले में पेश होने के लिए नोटिस दिया है, जिसको लेकर कुमार ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया था। विशेष अदालत ने कहा, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

उधर, सीबीआइ ने राजीव कुमार पर शिकंजा कसते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजीव बार-बार सीबीआइ के समन की अनदेखी कर रहे हैं। सीबीआइ टीम राजीव का पता लगाने के लिए संभावित जगहों पर छापामारी भी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को राजीव कुमार को सारथा चिटफंड घोटाले मामले में



राजीव कुमार

फाइल

► **जिला सत्र अदालत ने कहा-यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है मामला**

गिरफ्तारी से रहत का अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया था। कोर्ट ने सीबीआइ के नोटिस को दर करने संबंधी कुमार की याचिका को भी खारिज कर दिया था। कुमार अंतर्रमान में बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। वह सारथा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए गतिवित्त विशेष जांच दल में शामिल थे। हाई कोर्ट ने 2014 में चिटफंड के अन्य मामलों के साथ इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर बबीता के दिल में जागा भाजपा प्रेम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेता भारतीय महिला पहलवान बबीता फोंगट के दिल में भाजपा प्रेम जाग गया। उन्होंने कहा कि उक्त कार्रवाई के बाद ही उनका मन बदला और उन्होंने भाजपा में शामिल होकर जन सेवा करने का फैसला लिया। उनकी अंतर्रआत्मा से आवाज आई कि भाजपा के हाथों में ही देश सुरक्षित है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोंगट ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर देश में लंबे समय से राजनीति हो रही थी। इसके दम पर कई राजनीतिक दलों ने खुद को जिंदा रखा हुआ था। चुनाव के समय में अनुच्छेद 370 हटाने की बातें तो होती थीं, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता था। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

► **अंतरराष्ट्रीय पहलवान फोंगट ने साझा की दिल की बात**

► **कहा- खेल हो या राजनीति, राष्ट्रहित मेरे लिए सबसे ऊपर**



भारतीय महिला पहलवान बबीता फोंगट।

फाइल

इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय कश्मीरवासियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। यही मेरे लिए राजनीति में दर्जग में प्वाइंट था। विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि खेल हो या राजनीति, उनके लिए हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे और रहेंगे।

बबीता फोंगट ने माना कि पुलिस विभाग की नौकरी करते समय वह सक्रिय राजनीति

नहीं कर सकती थीं। उन्हें राजनीति जनसेवा का अच्छा माध्यम लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका परिवार इस फैसले से सहमत है। बबीता ने कहा कि वह शुरू से ही राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 1991 से कर दी थी। भविष्य में पार्टी जो निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा।

8 नवंबर तक कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट अब पांच नवंबर को मुकुल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

अकाली दल लड़ेगा हरियाणा विस चुनाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया है। यह फैसला मंगलवार को पार्टी की कोर कमेट्री की मीटिंग में लिया गया। कोर कमेट्री की ओर से लिए फैसलों के बारे में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हरचरन सिंह बैंस ने बताया कि पार्टी ने 22 सितंबर को चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए कुरुक्षेत्र में बैठक बुलाने का फैसला किया है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंदर सिंह भूंदड़ के नेतृत्व में एक स्क्लीमिंग कमेट्री बनाई गई है। कमेट्री भाजपा से सीटों के बंटवारे पर विचार-विमर्श करेगी। हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए बनाई इस कमेट्री के बाकी सदस्यों में प्रो. प्रेम सिंह चंद्रमाजरा व सुरजीत सिंह रखड़ा शामिल हैं।

बैंस ने बताया कि कोर कमेट्री ने विशेष प्रस्ताव पारित किया है। पहले प्रस्ताव में अकाली दल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सजा पूरी करने के बाद भी देश की विभिन्न जेलों में कैद सभी सिख कैदियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए जाएं। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री गुरु नानक



सुखबीर सिंह बादल

फाइल

► **पार्टी की कोर कमेट्री की मीटिंग में लिया गया फैसला**

► **भाजपा से सीटों के बंटवारे के लिए बात करेंगे वरिष्ठ नेता बलवंदर सिंह भूंदड़**

देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर इन सिसों व अन्य पंजाबी कैदियों की अन्यायपूर्ण व असंवैधानिक कैद को समाप्त करने का आग्रह किया है।

पंजाब के आग्रह पर हांसी

बुटाना लिंक नहर मामले

में कोर्ट ने दिया वक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हांसी बुटाना लिंक नहर मामले में पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसे लेकर हरियाणा और राजस्थान के साथ समझौते पर बातचीत चल रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील एके गांगुली के अनुरोध पर मामले की सुनवाई चार महीने के लिए टाल दी।

हरियाणा ने राज्य के दक्षिणी हिस्से को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से हांसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण कराया था। नहर वर्ष 2007 में बन गई थी, लेकिन पंजाब ने विरोध कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने नहर में पानी चालू करने पर रोक लगा दी थी, जो अब तक जारी है।

पंजाब सरकार के वकील गांगुली ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि समझौते के मद्देनजर केंद्र सरकार तीनों राज्यों के बीच बैठक और बातचीत करा रही है। उधर, हरियाणा की ओर से पेश वकील पुरुषेष्ट कौरव और अनीस गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि मुकदमा सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय कर दे। इस बीच समझौते की कोशिशें भी चलती रहें, लेकिन कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तिथि तय करने की बजाय सुनवाई चार महीने के लिए स्थगित कर दी।

हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर पंजाब की बड़ी आपत्ति यह है कि इसके चालू होने से उसके यहाँ बाढ़ आ जाएगी। हालांकि, हरियाणा का कहना है कि वह उसे मिल रहे पानी को ही दक्षिणी हिस्से को बांटेगा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी रहती है। पंजाब के विरोध पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहर को भाखड़ा मेन लाइन से जोड़ने पर रोक लगा रखी है।

► **मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा**

► **अव देशभर के मदरसों में सिखाई जाएंगी स्काउट-गाइड की गतिविधियां**



पचमढ़ी में स्काउट का प्रशिक्षण लेते मदरसों के मौलाना।

नईदुनिया

बताया कि स्काउट-गाइड के नौ नियम इस्लाम के अनुरसार हैं। इन पर चलकर मुस्लिम बच्चे देश और समाज को नई दिशा देंगे।

देश के युवाओं को फौज, पुलिस और शे। इन सभी ने स्काउट का कामिश्नर स्तर का है। इस प्रशिक्षण में शामिल सभी मौलानाओं ने स्काउट की वर्दी में सारी गतिविधियां और

एसजीपीसी और पंजाब सरकार एकसाथ मनाएंगी प्रकाश पर्व : लोंगोवाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, अमृतसर : पंजाब में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर प्रस्तावित समारोह मनाने को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री और पंजाब सरकार में कुछ समय से चल रहा विवाद सोमवार को तालमेल कमेट्री की बैठक में खत्म हो गया। बैठक के बाद एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि पंजाब सरकार और गुरुद्वारा कमेट्री इसे संयुक्त तौर पर मनाएंगी। इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर दोनों पक्षों की बैठक एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय में हुई।

लोंगोवाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी का अच्छा माध्यम लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका परिवार इस फैसले से सहमत है। बबीता ने कहा कि वह शुरू से ही राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 1991 से कर दी थी। भविष्य में पार्टी जो निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा।

कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में मजबूत होंगे गहलोत

नरेंद्र शर्मा, जयपुर

दस साल बाद एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगारी देखने को मिली। बसपा विधायक दल का कांग्रेस में विलय करने के बाद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मैं मैजिशियन तो हूँ ही। सीएम के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में गहलोत ने साल 2009 में बसपा के सभी छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करते हुए पूरे बसपा विधायक दल का पार्टी में विलय करा लिया था। सोमवार देर रात एक बार फिर गहलोत ने यही जादू दिखाया और बसपा के सभी छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया।

यह भी एक संयोग रहा कि तब भी बसपा के छह विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब 2019 में भी बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में गहलोत मजबूत होंगे। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ चल रहे शह और मात के खेल में अब गहलोत भारी हो गए हैं। अब तक 101 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल में पायलट समर्थक विधायकों की संख्या

भाजपा बोली-गहलोत के मन में असुरक्षा

► **प्रथम पुष्ठ से आगे**

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने का निर्णय सीएम अशोक गहलोत के मन में असुरक्षा दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रलोभन देकर गहलोत ने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया है।

आरएलडी का विधायक भी धामेगा हाथ : बसपा के सभी छह विधायकों के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के विधायक डॉ. सुभाष गर्ग भी कांग्रेस में शामिल होंगे। डॉ. गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले दो दशक से काफी निकट हैं।

दो निर्दलीय विधायकों को भी मिल सकता है मंत्री पद : वर्तमान में 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इनमें दो बाबूलाल नागर और राजकुमार गौड़ गहलोत के खास हैं। वहीं संयम लोढ़ा डॉ. सीपी जोशी के निकट हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नागर और लोढ़ा को मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है।

मायावती ने कांग्रेस को वातया घोखेबाज : बसपा के सभी छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज मायावती ने कांग्रेस को गैर-भरोसेमंद और घोखेबाज पार्टी करार दिया है। एक के बाद एक तीन

उपचुनाव के लिए बनाई प्रचार कमेटियां

बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद व दाखा उपचुनाव के लिए भी प्रचार कमेटियां बनाईं। पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ अकाली नेता जनमेजा सिंह सेखों जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार अध्यक्ष होंगे और डॉ. दलजीत सिंह वीमा दाखा के लिए बनाई प्रचार कमेट्री का नेतृत्व करेंगे।

पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने की बात दोहराई

बैंस ने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव में अकाली दल ने अपनी संघीय सोच का संकल्प करते हुए पंजाबी भाषा की संभाल व बढ़ावा देने संबंधी अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को दोहराया है। पार्टी ने कहा कि पंजाबी भाषा को महान गुरु साहिबान ने इस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम अंग बना दिया है। पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है कि पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाएं हमारी संघीय व लोकतांत्रिक राजनीति के समृद्ध बहुसांस्कृतिक किरदार का अटूट अंग हैं।

उपचुनाव और निकाय चुनाव में होगी परीक्षा

बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में आने का फायदा पार्टी को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, नागौर जिले की खीवसर और झुझुनू जिले की मंडावा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के साथ ही 52 शहरी निकायों के चुनावों में कांग्रेस को विलय से कुछ फायदा जरूर होगा। हालांकि, बसपा के कमिटेड वोट बैंक को ये विधायक कांग्रेस की तरफ कितना मोड़ पाएंगे इसकी परीक्षा दो विधानसभा उपचुनावों और निकाय चुनावों में हो जाएगी।

अधिक थी। गहलोत कांग्रेस आलाकमान के विश्वास के चलते सीएम बन गए थे। अपने समर्थक विधायकों की अधिक संख्या के कारण पायलट समय-समय पर गहलोत के सामने संकट खड़े करते रहते थे, लेकिन बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से गहलोत कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में मजबूत होंगे। पायलट के साथ चल रही खींचतान के चलते गहलोत सरकार में अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर पा रहे थे, प्रत्येक मामले को लेकर आलाकमान के पास पहुंचना पड़ता था।

200 विस सदस्यों वाले प्रदेश में दलीय स्थिति		
पार्टी	सीट	
कांग्रेस	106	
भाजपा	72	
निर्दलीय	13	
माकपा	02	
आरएलपी	02	
बीटीपी	02	
आरएलडी	01	
रिक्त सीटें	02	

ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस को बिना शर्त बाहर से समर्थन दे रही थी, उसके बाद भी उसने धोखा दिया। प्रजापति का कहना से लड़ने के बजाय हर जगह उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी है। अलास कर देना चाहिए। प्रजापति का कहना है कि कांग्रेस की वजह से डॉ. भीमराव आंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस की वजह से बाबा साहेब कबी लोकरसभा में चुनकर नहीं आ सके। न ही कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न दिया।

उत्तर प्रदेश में आरक्षण की जंग में बढ़ रहा जातियों के बीच बैर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कानून के दर पर चल रही आरक्षण की जंग समाज में लकीरें खीन करती जा रही है। अनुसूचित जाति का लाभ पाने को प्रयासरत 17 जातियों की रह में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित संस्थाएं रेंड़ा बन रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका खाते के बाद अब अति पिछड़ी जातियों के पैगैकार ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश लागू करने की याचिका दाखिल करने जा रहे हैं,

हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आदेश जारी किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।

► **ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश लागू कराने को कोर्ट जाएंगी 17 जातियों के झंडाबंदरदार**

► **आरक्षण का लाभ पा रही जातियों में से क्रीमीलेयर को छंटने की है आयोग की रिपोर्ट**

दो। इसके बाद से अब अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलनकारी नई जंग के लिए कमर कस चुके हैं।

इस मुद्दे पर हाल ही में उप्र के विभिन्न जिलों में न्याय संगोष्ठी कर चुके दलित शोषित पिछड़ा अधिकार दल की बैठक मंगलवार को बुलंदशहर में हुई। इसमें कहा गया कि पार्टी में तथ्य छिपाकर यह निर्णय करया गया है। स्टे खारिज कराने के लिए याचिका दायर किया जाएगा। इसके अलावा ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश लागू करने

के लिए अलग याचिका दायर की जाएगी। दल के महासचिव नीरज प्रजापति ने बताया कि आयोग द्वार 90 के दशक में दी गई अलास रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुसूचित वर्ग की कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व अपनी आबादी से कई गुना हो चुका है। इन्हें क्रीमीलेयर के फार्मूले से आरक्षण से अलास कर देना चाहिए। प्रजापति का कहना है कि 17 जातियों के खिलाफ एक जाति सबसे ज्यादा सक्रिय है, जबकि उप्र में सबसे अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व इसी जाति का हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा।

ये हैं 17 जातियां : कहर, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुल्हा, गोड़िया, मांझी और मछुआ।

जन्मदिन पर इस अंदाज में नजर आए मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में मनाया। यहां मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वह मंदिर भी गए और सरदार सरोवर बांध भी। सरदार सरोवर बांध के दीदार के दौरान उनके मुंह से दो ही शब्द निकले, अद्भुत...अविस्मरणीय। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को जनसरोकारों की याद दिलाई। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर उनका खास जोर रहा।



दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गरुडेश्वर दत्त मंदिर में पूजा- अर्चना के साथ की। वह यहां कुछ देर तक भक्ति-भाव के साथ खड़े रहे • प्रेट



नर्मदा नदी के ऊपर बने सरदार सरोवर बांध की खूबसूरती ने प्रधानमंत्री का मन मोह लिया • एएनआइ



बटरफलाई गार्डन में सैकड़ों तितलियों को एक बैग से निकालकर आजाद करने का कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। यह सोशल मीडिया में छाया रहा • प्रेट



प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देव व्रत और मुख्यमंत्री विजय रुपणीा के साथ जंगल सफाई में चल रहे कार्य का निरीक्षण भी किया • एएनआइ

कश्मीर पर फैसले के लिए पटेल से मिली प्रेरणा बोले पीएम

► नर्मदा की आरती उतार केवडिया को प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन का संगम बताया

69वें जन्मदिन पर गुजरात स्थित सरदार सरोवर बांध पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 69 वर्ष के हो गए। इस खास मौके पर वह अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। नर्मदा जिले के केवडिया स्थित सरदार सरोवर बांध का जायजा लिया, जिसका जल सत्र पहली बार उसकी क्षमता 138.68 मीटर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने नर्मदा मैया की आरती उतारी और अपनी मां का आशीर्वाद लिया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सरदार सरोवर बांध को बिजली की लड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ भी गए। सजे सवरे बांध, लबालब भरे पानी और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखकर प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले- अद्भुत, अविस्मरणीय।

प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए देश के पहले गृह मंत्री सरकार बल्लभ

न्यूज गेलरी

टार्व और मोबाइल की रोशनी में हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग

गढ़वा : हम सबने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को कई विपरीत परिस्थितियों में लैंडिंग करते देखा होगा। लेकिन सोमवार रात झारखंड के गढ़वा में स्थित हेलीपैड पर सीआरपीएफ जवानों ने अपने बीमार साथी को इलाज के लिए रांची भेजने के लिए टार्व और मोबाइल की रोशनी का सहारा लिया। रात के अंधेरे में हेलीपैड की लोकेशन पता करने में हेलीकॉप्टर के पाइलट को परेशानी हो रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ जवानों ने हेलीपैड के निकट टार्व और मोबाइल से रोशनी कर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतारने में पायलट की बखूबी मदद की। इससे न केवल हेलीकॉप्टर का हेलीपैड पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, बल्कि बीमार जवान सुदामा प्रसाद यादव को इस हेलीकॉप्टर में बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा जा सका। (जास)

कोयला घोटाले में सीबीआइ और ईडी से स्थिति रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान के आवंटन घोटाले की जांच कर रही जी एंजेंसियों सीबीआइ और ईडी से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले पर अदालत में सुनवाई की स्थिति पर भी जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा है कि कोयला घोटाले की जांच के मामलों में एफएसरो के खदेश आगमन पर व्यवहारिक विचार रखने की जरूरत है। एंजेंसियों की इस रूप में जांच जारी है कि जांच बाधित न हो। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें मामले की फाइलों को खंगालने की जरूरत है। चुंकि नई खंडपीठ इस मामले को देख रही है और वह सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर को सुबीबद्ध हुई है। खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चोप्रा की सहायता मांगी है। कोयला घोटाले के मामलों में सर्वोच्च अदालत ने विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नियुक्त किया है। (प्रेट)

चिन्मयानंद प्रकरण

कभी भी हो सकता है पूर्व केंद्रीय मंत्री पर मुकदमा, सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए थे बयान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा की सुस्था और कड़ी कर दी गई। एसआइटी (विशेष जांच दल) के निर्देश के बाद घर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

मंगलवार को छात्रा किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा कि सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद किसी कामज पर हस्ताक्षर रह गए थे। इसीलिए, वह मंगलवार को पिता व एसआइटी के एक अधिकारी के साथ कोर्ट पहुंची। सोमवार को छात्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गीतिका सिंह की कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। इससे पहले 161 के तहत पुलिस के सामने भी बयान हो चुके थे। जिसके बाद माना जाने लगा कि कभी भी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जाने लगी है। हालांकि अभी इस बाबत एसआइटी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही। मगर, जिस तरह से छात्रा की सुस्था कड़ी की जा रही

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

मेडिकल के छात्र फंस गए हैं तीन दिन पूर्व उग्र के सहारनपुर स्थित शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में वीयर पार्टी कर हंगामा करने के मामले में ।

रह था। आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन सुक्ष्म सिंचाई के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2001 में जब वे गुजरात के सीएम बने तब बिजली उनकी पहली प्राथमिकता थी, 26 फीसदी घरों को नल से पानी मिलता था लेकिन अब 78 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच रहा है, अब देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है।

नर्मदा मैया की आरती की : इससे पहले मोदी ने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। मोदी ने कहा कि केवडिया प्रकृति, पर्यावरण व पर्यटन का त्रिवेणी संगम है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, सफारी पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफलाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग लोगों को बरन्स ही यहां खींच लाती है। मोदी ने कहा 133 साल पहले बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हर माह औसतन द स हजार लोग देखने आते हैं लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 11 माह में ही हर माह 8500 लोग देखने आने लगे हैं। अब तक 23 लाख से अधिक पर्यट देश और दुनिया से यहां आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है।

नर्मदा मैया की आरती की : इससे पहले मोदी ने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। मोदी ने कहा कि केवडिया प्रकृति, पर्यावरण व पर्यटन का त्रिवेणी संगम है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, सफारी पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफलाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग लोगों को बरन्स ही यहां खींच लाती है। मोदी ने कहा 133 साल पहले बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हर माह औसतन द स हजार लोग देखने आते हैं लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 11 माह में ही हर माह 8500 लोग देखने आने लगे हैं। अब तक 23 लाख से अधिक पर्यट देश और दुनिया से यहां आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है।

नर्मदा के जल से गुजरात को नया जीवन

इकबाल पर दर्ज होगा देशद्रोह का मुकदमा

जागरण संवाददाता, अयोध्या

बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के विरुद्ध देशद्रोह, मारपीट व धमकी देने का मुकदमा रामजन्मभूमि थाने में दर्ज होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेन्द्र प्रताप सिंह ने खुद को अंतरराष्ट्रीय शूटर बताने वाली वार्तिका सिंह की याचिका को कोर्ट के आदेश पर कटौत दिया है। मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में प्राथमिकी की प्रति और कार्रवाई की आख्या भी मांगी है।

इकबाल और वार्तिका विवाद पर फैसला सुनने के लिए मंगलवार को अदालत खचाखच भरी थी। अलंबा, वार्तिका वहां नहीं थीं। उनके अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी व पवन तिवारी ने याचिका को कोर्ट के आदेश पर कटौत दिया है। मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में प्राथमिकी की प्रति और कार्रवाई की आख्या भी मांगी है।

यदि मस्जिद है तो वहां फूल जानवर आदि चित्रित नहीं होने चाहिए

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस बहस से पहले जब धवन अपना दावा साबित करने के लिए कोर्ट का ध्यान 1950 कदीर खां अश्लील हरकत करते हैं। सुनते ही परिजनों का पास चढ़ गया। वे प्रिंसिपल कदीर के पास पहुंचे। शिकायत सुनने के बजाय उसने उन्हें धक्के देकर कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। इस पर बच्ची के परिजन लौट गए। कुछ देर बाद वे दोबारा स्कूल पहुंचे। कुछ छात्राओं से बातचीत की। उन लोगों ने बताया प्रिंसिपल उनसे भी कई बार गंदी हरकत कर चुका है। बच्चियों की इस बातचीत का वीडियो बनाने के बाद वे कोतवाली पहुंचे और पुलिस को वीडियो दिखाया।

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीड़ित छात्रा : चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा आगे की पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड

विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है।

मेडिकल के छात्र फंस गए हैं तीन दिन पूर्व उग्र के सहारनपुर स्थित शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में वीयर पार्टी कर हंगामा करने के मामले में ।

रह था। आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन सुक्ष्म सिंचाई के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2001 में जब वे गुजरात के सीएम बने तब बिजली उनकी पहली प्राथमिकता थी, 26 फीसदी घरों को नल से पानी मिलता था लेकिन अब 78 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच रहा है, अब देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है।

नर्मदा मैया की आरती की : इससे पहले मोदी ने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। मोदी ने कहा कि केवडिया प्रकृति, पर्यावरण व पर्यटन का त्रिवेणी संगम है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, सफारी पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफलाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग लोगों को बरन्स ही यहां खींच लाती है। मोदी ने कहा 133 साल पहले बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हर माह औसतन द स हजार लोग देखने आते हैं लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 11 माह में ही हर माह 8500 लोग देखने आने लगे हैं। अब तक 23 लाख से अधिक पर्यट देश और दुनिया से यहां आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है।

राज्य ब्यूरो, जम्मु

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय सेना के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। उन्होंने लद्दाख में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लेह में क्रिकेट स्पोर्ट्स अकादमी खोलने की भी घोषणा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में अपने पहले दौर के दौरान मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने खारदुंगला पास पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से प्लास्टिक को नकार पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री के साथ लद्दाख में मातृभूमि की रक्षा कर रहे सेना के जवानों ने भी पर्यावरण संरक्षण अभियान में हिस्सा लेकर संदेश दिया कि वे देश की सरहदों की रक्षा करने के साथ ही इसे साफ-सुथरा रखने के प्रति भी गंभीर हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लेह में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

मुस्लिम महिलाओं को भाए मोदी के फैसले, मनाया जश्न

रामपुर : मोदी सरकार के फैसले मुस्लिम महिलाओं को खूब वा रहे हैं। पहली बार देखने को मिला, जब हजारों मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जश्न के

मेडिकल के छात्र फंस गए हैं तीन दिन पूर्व उग्र के सहारनपुर स्थित शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में वीयर पार्टी कर हंगामा करने के मामले में ।

रह था। आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन सुक्ष्म सिंचाई के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2001 में जब वे गुजरात के सीएम बने तब बिजली उनकी पहली प्राथमिकता थी, 26 फीसदी घरों को नल से पानी मिलता था लेकिन अब 78 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच रहा है, अब देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है।

नर्मदा मैया की आरती की : इससे पहले मोदी ने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। मोदी ने कहा कि केवडिया प्रकृति, पर्यावरण व पर्यटन का त्रिवेणी संगम है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, सफारी पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफलाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग लोगों को बरन्स ही यहां खींच लाती है। मोदी ने कहा 133 साल पहले बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हर माह औसतन द स हजार लोग देखने आते हैं लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 11 माह में ही हर माह 8500 लोग देखने आने लगे हैं। अब तक 23 लाख से अधिक पर्यट देश और दुनिया से यहां आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है।

नर्मदा के जल से गुजरात को नया जीवन

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीड़ित छात्रा : चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा आगे की पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड

विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है।

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीड़ित छात्रा : चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा आगे की पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड

विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है।

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीड़ित छात्रा : चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा आगे की पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड

विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है।

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

पर चिन्मयानंद को बदनमान किया गया। इस प्रकरण से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे

थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों भाई दुरीश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस लाईंस स्थित अस्थायी कार्यालय बुलाया था। अभी

तीनों हिरासत में हैं।

रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीड़ित छात्रा : चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा आगे की पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड

विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है।

है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है।

अब इनने पुलिसकर्मों तैनात व चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व

परिवार के सदस्यों की जान को खराब बताया था। जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कॉन्स्टेबल, दो

महिला कॉन्स्टेबल व चार पुरुष कॉन्स्टेबल उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार को एसआइटी के निर्देश पर चार कॉन्स्टेबल व दो

एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों भाई

: इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने

‘नए मोटर वाहन कानून पर मिल रहा सभी राज्यों का समर्थन’

नई दिल्ली, प्रेट : नए मोटर वाहन कानून पर सभी राज्यों का समर्थन मिल रहा है। कमोवेश प्रत्येक व्यक्ति नए कानून का स्वागत कर रहा है और उम्मीद है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह दावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को किया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी दंड के प्रावधान वाला मोटर वाहन (नशोधन) अधिनियम, 2019 एक सितंबर से लाग



तेजी से सामान्य हो रहे हालात

जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालात सामान्य हो चले हैं।मंगलवार को श्रीनगर में पाबंदियों में ढील के साथ सड़कों पर वाहनों का आवागमन सुचारु नजर आरहा।

प्रेट्र

आतंकियों को ढेंगा, नैफेड को सेब बेच रहे किसान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में नैफेड की खरीद प्रक्रिया शुरू होने से सेब उत्पादक बेहद उत्साहित हैं। वहीं, जिहादी और राष्ट्र विरोधी तत्व पूरी तरह बौखला गए हैं। पिछले चार दिन में दक्षिण कश्मीर में कुछ जगहों पर आतंकियों द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने और सेब की पेटियों को जलाने की सूचनाएं आई हैं। इसके बावजूद कश्मीर के सेब उत्पादक आतंकियों की धमकियों व फरमानों को ठेंगा दिखा रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ पांच दिन में करीब 500 सेब उत्पादक बागवानी विभाग के पास अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और 10 हजार पेटि सेब खरीदा भी जा चुका है।

पांच अगस्त के बाद से कश्मीर में कानून व्यवस्था की उपजी स्थिति में आतंकियों ने स्थानीय सेब उत्पादकों को फरमान सुना रखा है कि वह देश की मंडियों को सेब न भेजें। इस फरमान को न मानने पर आतंकियों ने पिछले दिनों सोपोर में सेब कारोबार से जुड़े तीन लोगों के अलावा एक ढाई साल की बच्ची को भी गोली मारी थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार

लगातार बढ़ रही पंजीकरण कराने वालों की संख्या

बागवानी निदेशक कश्मीर एजाज अहमद बट ने दैनिक जागरण को बताया कि बहुत से सेब उत्पादक हमारे पास पंजीकरण कराने आ रहे हैं। हमें आज परिपोरा में एक नया काउंटर बनाना पड़ा है, जिस पर बुधवार से खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान इस मूल्य पर हमें अपनी फसल नहीं बेचना चाहता तो वह बाजार में खुद भी बेच सकता है।

के आग्रह और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर नैफेड ने स्थानीय सेब उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रत्येक ग्रेड का सेब खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इस योजना से कश्मीर में करीब सात लाख किसान लाभान्वित होंगे।

पहले चरण में अनंतनाग, श्रीनगर और सोपोर में बनाई गई हैं मंडियां : पहले चरण में किसानों से सेब की सीधी खरीद के लिए अनंतनाग, श्रीनगर और सोपोर में मंडियां बनाई

5 दिनों में 500 उत्पादकों ने कराया पंजीकरण, 10 हजार पेटि सेब खरीदा, आतंकियों की ओर से सेब की फसल को नुकसान पहुंचाने की सूचना



सुरक्षा के और कड़े बंदोबस्त किए जाएं

शोपिया निवासी फैयाज अहमद ने कहा कि अभी हमारे यहां सरकार ने मंडी स्थापित नहीं की है। कुछ छोटे किसानों की सेब की फसल तैयार है और वह बटेगू, अनंतनाग की मंडी में जा रहे हैं। डर है कि जिहादी शोपिया में मंडी लगने के बाद हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सुरक्षा के और कड़े बंदोबस्त किए जाएं।

गई हैं। इन मंडियों को लेकर विशेषकर छोटे और मझोले किसानों में जबरदस्त उत्साह है। फल व्यापारी अपनी फसल बागवानी विभाग के सहयोग से नैफेड द्वारा स्थापित मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं।

फसल को पहुंचाया नुकसान, कहीं लगाई आग : हताशा आतंकियों ने पिछले चार दिन में दक्षिण कश्मीर के अकिनगाम में एक बाग को नुकसान पहुंचाने के अलावा दो सेब उत्पादकों द्वारा मंडी में पहुंचने के लिए तैयार रखी गई

सेब की पेटियों को आग लगा दी। क्षतिग्रस्त बाग के मालिक के नुकसान की भरपाई के लिए कम से 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि पेड़ के सही तरीके से तैयार होने में समय लगता है। इसके अलावा जिन किसानों की सेब पेटियां जलाई गई हैं, उन्हें 75 हजार से लेकर दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। किसान आतंकियों की इन नापाक हरकतों से डरे नहीं हैं। वे नैफेड की सीधे सेब बेचकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।

नृपेंद्र हो सकते हैं पहले उपराज्यपाल

सियासी सरगर्मी ▶ राज्यपाल के दो सलाहकार और खुफिया विभाग के अधिकारी भी दौड़ में

31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे

जम्मू- कश्मीर और लद्दाख

नवीन नवाज, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के सृजन के साथ ही राज्य की कमान पहले उपराज्यपाल संभाल लेंगे। फिलहाल चयन प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है लेकिन दावेदारी अभी से जताई जा रही है। सियासी हलकों में चर्चा है कि अगर राज्यपाल सत्यपाल मलिक तैयार नहीं होते हैं तो नृपेंद्र मिश्रा जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मलिक को दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अलबत्ता, प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या यकीन दिलाया है, यह वही जानते हैं।

केंद्र चाहता है एक उपराज्यपाल : वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार केंद्र दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उपराज्यपाल की नियुक्ति का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि कई पूर्व सैन्य



सत्यपाल मलिक।

(फाइल)

राज्यों का उपराज्यपाल बनाने का संकेत दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि मलिक किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण के इच्छुक हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अलबत्ता, प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या यकीन दिलाया है, यह वही जानते हैं।

केंद्र चाहता है एक उपराज्यपाल : वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार केंद्र दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उपराज्यपाल की नियुक्ति का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि कई पूर्व सैन्य



नृपेंद्र मिश्रा।

(फाइल)

अधिकारी, पूर्व नौकरशाह और राज्यपाल की सलाहकार परिषद के सदस्य भी दौड़ में हैं। इनके अलावा कश्मीर पर केंद्रीय वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है।

अभी दौड़ में आगे हैं मिश्रा : अभी तक समीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के पक्ष में बनते दिख रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल मलिक अगर जम्मू-कश्मीर में नहीं रुकना चाहेंगे तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की पहली पसंद नृपेंद्र मिश्रा है। उन्होंने

गत माह अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। 1967 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आइएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा मई 2014 से अगस्त 2019 तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं। 2005 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह ट्राई (टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) के अध्यक्ष भी रहे। वह वाशिंगटन में वर्ष 1985-88 तक भारतीय दूतावास में आर्थिक मामलों के प्रभारी भी रहे हैं।

के. विजय कुमार और फारूक खान भी हैं रेस में : राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार और फारूक अहमद खान दोनों ही पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। के. विजय कुमार चंदन तस्कर वीरप्पन को मार गिराने के अभियान से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी योग्यता का परिचय दे चुके हैं। वह कश्मीर में भी बतौर बीएसएफ अधिकारी सेवाएं दे चुके हैं। फारूक अहमद खान जम्मू के ही रहने वाले हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने में अहम भूमिका निभाने वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन में अहम भूमिका निभाई है। वह राज्यपाल का सलाहकार बनने से पूर्व लक्षद्वीप में प्रशासक थे।

पूर्वी लद्दाख में एकीकृत युद्धाभ्यास में शामिल हुए आर्मी कमांडर



सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पूर्वी लद्दाख में सेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास का निरीक्षण करते हुए।

राज्य ब्यूरो, जम्मू

लद्दाख के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करने की मुहिम जारी है। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में सेना के एकीकृत युद्धाभ्यास में शामिल हुए। पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भारतीय सेना के बड़े में आधुनिक उपकरणों को शामिल किया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आर्मी कमांडर ने सेना के सभी अंगों के युद्धाभ्यास का

हिस्सा बनकर ऑपरेशनल तैयारियों का जायज लिया। आर्मी कमांडर ने आधुनिक टी-90 भीएम टैंक की सवारी कर इसकी मारक क्षमता का जायजा लिया। यह टैंक रात के समय भी सटीक गोलाबारी करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही रूस में बने टैंकों को भी भारतीय सेना के बड़े में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के सामने खड़ी सेना को मजबूत करना समय की मांग है। ऐसे में मोदी सरकार भावी चुनौतियों को देखते हुए लद्दाख में सेना की मारक क्षमता को कई गुणा बढ़ाने की मुहिम पर है। 1

इसी हफ्ते जम्मू- कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं आजाद, स्थानीय नेता उत्साहित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नए एजेंडे और नारे के साथ अपनी सियासी गतिविधियां शुरू कर सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जल्द जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि अभी आजाद के कश्मीर के प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा और समय तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वह इसी हफ्ते कश्मीर आ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आजाद अपने दौरे के दौरान श्रीनगर, जम्मू, बारामुला और अनंतनाग जाएंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। वह कोई सियासी जनसभा या रैली नहीं करेंगे। इसके अलावा घोषित तौर पर किसी सियासी बैठक का भी हिस्सा नहीं बनेंगे।

स्थानीय सियासी हलकों में पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सोमवार शाम से ही कई अटकलें चल रही हैं। दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के एक पूर्व एमएलसी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। लोग इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं और आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में हमारी ही नहीं आम लोगों की भी पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत होगी। इसलिए कह सकते हैं कि जल्द जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की सियासी गतिविधियों में बदलाव और तेजी

डेड माह से लगभग ढप कांग्रेस की सियासी गतिविधियां पकड़ेंगी जोर बढ़ते परिवेश में नए एजेंडे के साथ लोगों में सामने आ सकती है कांग्रेस



गुलाम नबी आजाद।

(फाइल)

देखने को मिलेंगी।

तीन बार एयरपोर्ट से लौटाए गए थे आजाद : पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित होने के बाद राज्य में पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीन बार आठ, 20 और 24 अगस्त को राज्य में आने का प्रयास किया था। तीनों ही बार उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट या फिर जम्मू एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया।

आजाद के दौरे की सूचना से पार्टी वर्कर और नेता उत्साहित हैं। बेशक कोई सियासी जलसा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो राज्य के हालात पर चर्चा होगी। दौरा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा। किसी तरह की सियासी बैठक नहीं की जाएगी। मगर पार्टी कार्यकर्ता अगर उनसे मिलना चाहेंगे तो मिल सकेंगे।

–मोहम्मद सुल्तान मंडु, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

गुलाम नबी आजाद के दौरे की रूपरेखा तय नहीं हुई है। अदालत के निर्देशानुसार, दौरा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा। किसी तरह की सियासी बैठक नहीं की जाएगी। मगर पार्टी कार्यकर्ता अगर उनसे मिलना चाहेंगे तो मिल सकेंगे।

–रविंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी

सर्वोच्च न्यायालय ने दौ दौरे की अनुमति : कांग्रेस नेता आजाद ने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश पर रोक लगाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें श्रीनगर, जम्मू, बारामुला और अनंतनाग का ने तीन बार आठ, 20 और 24 अगस्त को राज्य में आने का प्रयास किया था। तीनों ही बार उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट या फिर जम्मू एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया।

कश्मीर में बिना वेरिफिकेशन मिल रहा आयुष्मान का लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के बाद भी गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने विशेष ब्यूट दे रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ इंदु भूषण के अनुसार कश्मीर में मरीजों का इलाज बिना ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ही किया जा रहा है। इससे जम्मू-कश्मीर के गरीब व बीमार लोगों का आसानी से इलाज हो पा रहा है।

55 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये सालाना तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की एक साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए हर्षवर्द्धन ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरो तालर्स का नतीजा है कि एक साल के भीतर ऐसे 338 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो गड़बड़ी कर रहे थे। इनमें 97 अस्पतालों को आयुष्मान भारत के पैन्ल से बाहर कर दिया है। कई अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुछ के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है।

इंदु भूषण ने कहा कि आयुष्मान भारत में गड़बड़ी में पकड़े गए अस्पतालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मसार करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे अस्पतालों को सीजीएचएच जैसी दूसरी योजनाओं व बीमा कंपनियों के पैन्ल से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। आयुष्मान योजना के तहत अभी तक 45 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 30 सितंबर और एक अक्टूबर को विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। हर्षवर्द्धन ने बताया कि गरीबों को मुफ्त इलाज के साथ ही सरकार आयुष्मान भारत के दूसरे भाग पर भी तेजी से काम कर रही है। इसके तहत 2022 तक डेढ़ लाख ब्लैक व वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं। अभी तक लगभग 21 हजार ऐसे सेंटर खोले जा चुके हैं और अगले साल 31 मार्च तक 40 हजार सेंटर खोलने का लक्ष्य है। इन सेंटरों में 30 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध होगी।

अखंडता की दास्तां सुना रहे गुलाम कश्मीर के ऐतिहासिक स्थल

लोकेश चौहान, नई दिल्ली :

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार देश में गुलाम कश्मीर को लेकर नई बहस शुरू हुई है। इस बीच पहली बार देश में एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व गुलाम कश्मीर के ऐतिहासिक स्थलों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। गुलाम कश्मीर के 28 स्मारकों में से 15 की तस्वीरों को राजधानी में सोमवार से आयोजित इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य स्मारकों के माध्यम से देश की एकता की तस्वीर पेश करना है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व गुलाम कश्मीर में कुल 55 स्मारक हैं। इनमें से 28 स्मारक गुलाम कश्मीर में हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुलाम कश्मीर के 15 स्मारकों की तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उधमपुर से सांसद व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के

राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी एनएमए के परिसर में ही लगाई गई है।

चुनौती

किश्तवाड़ में एक साल से सुरक्षाबलों को चकमा दे रहे चार आतंकी, गुप्तचर एजेंसियों को भी नहीं मिल पा रहे आतंकियों के पुख्ता सबूत

क्यों सुरक्षाबलों के हथ्थे नहीं चढ़ रहे मुट्‌ठी भर आतंकी

बलवीर सिंह जग्गल, जम्मू

जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में गिने-चुने ही आतंकी सक्रिय हैं। तीन ही आतंकी हैं, जिन्होंने एक वर्ष के अंदर चार बड़ी वारदात को अंजाम देकर सुरक्षाबलों की नींद हराम कर दी है। चौथा आतंकी अप्रैल में इस गुट में मिला है। सुरक्षाबल और पुलिस इन मुट्‌ठी भर आतंकियों को दबोचने में विफल साबित हो रहे हैं।

किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राइफल की तीन बटालियन हैं। दो बटालियन सीआईएसएफ, एक बटालियन सीआरपीएफ और पिछले आठ महीने से एक बटालियन आइटीबीपी की भी तैनात है। इसके अलावा स्पेशल ड्यूटी पर आए सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षाबलों और पुलिस को मिलाकर हजारों सुरक्षाबल किश्तवाड़ में तैनात हैं। इसके अलावा कई गुप्तचर एजेंसियां भी काम कर रही हैं। इसके बावजूद चार आतंकी किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहे। आतंकी हर बार नया प्लान बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं। बीते शुक्रवार को हुई वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आतंकी पुलिस

आतंकियों पर नजर

ओसामा बिन जावेद : हर गली मोहल्ले का जानकार

किश्तवाड़ में सक्रिय आतंकी ओसामा बिन जावेद किश्तवाड़ की मड़वा तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। दो साल पहले ही आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हुआ है। पिछले कई वर्षों किश्तवाड़ में ही रहा है। स्थानीय लोगों के साथ उठना-बैठना भी है। इसके अलावा वह किश्तवाड़ के हर गली-मोहल्ले का जानकार है।

हारुन बानी : एमबीए करने के बाद बना आतंकी

हारुन बानी जम्मू संभाग के डोडा जिले के घाट गांव का रहने वाला है। एक साल पहले ही एमबीए करने केबाद आतंकी बन गया था। वह ओसामा बिन जावेद के साथ मिलकर काम कर रहा है। किश्तवाड़ में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में उसने सक्रिय भूमिका निभाई है।

सुरक्षाबल और खुफिया एजेंसियां अब इसी थ्योरी पर काम कर रही हैं। एजेंसियों का मानना है कि आतंकी वारदात से पहले ओजीडब्ल्यू से रेकी करवाते हैं। उसके बाद वारदात को अंजाम देकर ओजीडब्ल्यू का सहारा लेकर फरार हो जाते हैं।

सुरक्षाबल अब आतंकियों के साथ ओजीडब्ल्यू को सरगमी से तलाश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किश्तवाड़ शहर से कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियां अपना अभियान और तेज करेंगी।

महाराष्ट्र में ‘ कड़कनाथ ’ के नाम पर करोड़ों का घोटाला, तीन गिरफ्तार

जालसाजी ► सांगली की कंपनी ने काले चिकन के नाम पर हजारों किसानों को टगा

कंपनी ने 20–60 रुपये में अंडे और 1200 रुपये किलो तक में चिकन खरीदने का किया था वादा

पुणे, प्रे्र : महाराष्ट्र के कई जिलों में एक पोल्ट्री फॉर्म के खिलाफ किसानों ने ‘कड़कनाथ’ प्रजाति के मुर्गों पैदा करने में मदद के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए हैं। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे के काले रंग के मीट की मध्य भात खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत मांग रहती है। इसे इसके पोषण और चिकित्सकीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। इसका चिकन 900 रुपये प्रति किलोग्राम तक में बिकता है। किसानों ने सांगली मुख्यालय वाली कंपनी महारायत एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया कि कंपनी ने कड़कनाथ प्रजाति के चूकों की संख्या बढ़ाने और बाद में मुर्गों को खरीदने की कारोबारी योजना के नाम पर उनसे भारी निवेश कराया। पुणे के दत्तावाड़ी थाने के सहायक पुलिस



प्रतीकात्मक फोटो

निरीक्षक शंकर सालगर ने पीटीआइ को बताया कि अभी तक कंपनी के खिलाफ सांगली, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, पालघर, नासिक और औरंगाबाद में मामले दर्ज कराए गए हैं। **550 करोड़ का घोटाला** : पुलिस अभी इस मामले में घोटाले की रकम का पता लगा रही है। पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेठ्ठी ने दावा किया है कि प्रदेश भर में 10 हजार से ज्यादा किसानों से लगभग 550 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग भी की है।

आरोपितों के एक नेता से संबंध :

उग्र में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सहित 176 ने दी गिरफ्तारी

जासं, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित घुन्ना व नांजिरपुरा गांव में हुए बवाल के बाद दर्ज हुई एफआइआर के विरोध में मंगलवार को भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सहित 176 लोग गिरफ्तारी देने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां मुस्तैद पुलिस-प्रशासन ने उन्हें बस में बैठाया और सभी को पुलिस लाइन मैदान ले गए। गिरफ्तारी देने वालों में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया की मां सहित 44 महिलाएं भी शामिल थीं। तहसीलदार को ज्ञापन दिलवाकर शाम को सभी को छोड़ दिया गया। वहीं, एक हफ्ते बाद भी पुलिस को किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आंबेडकर प्रतिमा तोड़ने के आरोपित भी नहीं पकड़े गए हैं।

10 सितंबर को बेहत रोड स्थित घुन्ना गांव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इससे गुस्साए घुन्ना व नांजिरपुरा के अनुसूचित जाति के लोगों ने बेहत रोड पर घंटों जाम लगाया था। पुलिसकर्मियों व शाकंभरी देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर पथराव कर दिया था। पुलिस ने 104 को नामजद करते हुए कुल

► **सहारनपुर के दो गांवों में हुए बवाल में दर्ज मुकदमों का किया विरोध**

► **आंबेडकर प्रतिमा तोड़ने के आरोपितों को अभी तक नहीं पकड़ सकी है पुलिस**

700 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसी के विरोध में भीम आर्मी ने एलान किया था कि आरोपितों के परिवारीजनों के साथ मंगलवार को वह सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। मंगलवार सुबह साढ़े 11 बजे जिलाध्यक्ष रोहितराज गौतम के नेतृत्व में करीब 100 लोग गिरफ्तारी देने के लिए कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। एसपी सिटी ने सभी को बस में बैठाया और पुलिस लाइन मैदान में भिजवा दिया। बाद में इन्हें शांतिभंग व धारा 144 के उल्लंघन के तहत कारवाई करते हुए निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।

उल्लेखनीय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर समेत कई जिलों में पहले भी अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वर्चस्व को लेकर होने वाले टकरावों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं।

चित्रदुर्ग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ डीआरडीओ का रुस्तम

- मानवरहित यान ‘रुस्तम-2’ का चल रहा था परीक्षण**
- हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल**



चित्रदुर्ग जिले में मंगलवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मानवरहित विमान (यूपीवी) दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

बेंगलुरु, प्रे्र : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का मानवरहित विमान (यूपीवी) मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुआ। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रण्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मानवरहित यान ‘रुस्तम-2’ का परीक्षण चल रहा था। इसे बीच वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीआरडीओ ने ट्वीट किया, ‘डीआरडीओ से विकसित किया जा रहा मानवरहित यान

करोड़ का जुर्माना लगाया गया है वैश्विक अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और छह अन्य पर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में यह कदम उठाया है।

230

कंपनी के संस्थापक और निदेशकों पर केस दर्ज

पुणे पुलिस ने इस महीने के शुरू में सांगली स्थित कंपनी के संस्थापक सुधीर मोहिते और दो निदेशकों हनुमंत जगदाले और संदीप मोहिते के खिलाफ 100 से ज्यादा किसानों से तीन करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इसी तरह सांगली के इस्लामपुर थाने में भी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ किसानों के साथ करीब 4.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि अब तक छह सौ से सात सौ किसानों ने कंपनी के निदेशकों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है।

मुख्य आरोपित फरार

पुलिस ने संदीप मोहिते, हनुमंत जगदाले और कंपनी के पुणे स्थित दफ्तर में अकाउंटेंट प्रीतम माने को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपित सुधीर मोहिते और दो अन्य बौद्धिंत आरोपित फरार हैं। इस मामले को अब सांगली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को ट्रान्सफर कर दिया गया है। एक शिकायतकर्ता नीलेश अंबेडे ने आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी की योजना में 2.5 लाख रुपये का निवेश किया था, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक कभी चुजे मिले ही नहीं।

राजू शेठ्ठी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में आरोपितों के एक राजनीतिक दल के बड़े नेता

से संबंध हैं। हालांकि, उन्होंने किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया है।

दुष्कर्म के बाद भी नाबालिग पीड़िता ने आरोपित से की थी फोन पर बात

- जागरण संवाददाता, पश्चिमी चंपारण**
- मुजफ्फरपुर वालिका गृह की पूर्व संवांसिन से सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार**
- मैडिकल जांच में नाबालिग निकली पीड़िता, 15 से 17 के बीच है उम्र**
- घटना के बाद भी पीड़िता ने आरोपित से मोबाइल पर बात की थी। शायद इन्हीं कारणों से घटना के करीब 15 घंटे बाद पीड़िता प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची।**
- पंकज कुमार, एसडीपीओ, बेतिया**

पीड़िता नाबालिग है। उसकी उम्र 15 से 17 के बीच हो सकती है।

सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम जानकारी : सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला है कि आरोपित पीड़िता ही गाड़ी सबसे पहले बैठी। उसने उसने सबका नाम भी बताया। चालक और आरोपित आकाश को फोन कर बुलाया था। बाद में अलग-अलग दो चौराहों पर गाड़ी रुकी, जिसमें तीन लोग सवार हुए थे। नगर थानाध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला है कि पीड़िता को अगवा नहीं किया गया था।

एनजीओ के हर सदस्य को बताना होगा–धर्मांतरण में नहीं हैं शामिल

नई दिल्ली, प्रे्र : विदेशी फंड हासिल करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को अब सरकार के समक्ष यह घोषित करना होगा कि वे कभी किसी व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिसूचना में मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) कानून (एफसीआर) में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब एक लाख रुपये तक के निजी उपहार प्राप्त करने वालों के लिए सरकार को इस आशय की सूचना देना जरूरी नहीं होगा। पहले यह राशि 25 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। मंत्रालय के मुताबिक, एनजीओ के प्रत्येक अहम सदस्य और पदाधिकारी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे किसी के धर्मांतरण के लिए न तो सजा सुनाई गई है और न ही दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा एफसीआरए 2010 के अनुसार केवल मंगलवार की सुबह सुपारी के बाग में गिरा। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।



उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं।

तब तक लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई थीं। ऐसे में सरकार को इससे कदम पीछे खींचने पड़े।

अब हरियाणा सरकार द्वारा एनआरसी को अपने प्रदेश में लागू करने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में विचार करने की बात कहने के बाद प्रदेश सरकार एक बार फिर इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह गवत ने मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य के मसले पर सरकार

विचार करेगी। उत्तराखंड के सीमांत प्रदेश होने के कारण यह मुद्दा संवेदनशील है। इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी और फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

उधर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी सरकार एक बार फिर इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह गवत ने मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य के मसले पर सरकार

5555 किमी की रफ्तार से दुश्मन तक पहुंचेगा ‘ अस्त्र ’

► **स्वदेशी तकनीक से निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल का ओडिशा के बंगोप सागर तट पर परीक्षण**

► **राजनाथ ने डीआरडीओ व सेना को दी बधाई**



ओडिशा के बंगोप सागर तट पर मंगलवार को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ‘अस्त्र’ का लड़ाकू विमान सुखोई से लॉंच कर सफल परीक्षण किया गया।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा के बंगोप सागर तट पर मंगलवार को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ‘अस्त्र’ का सफल परीक्षण किया गया। ‘अस्त्र’ पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों से निर्मित पहली एयर टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल सुपर सोनिक गति से हवा में उड़ रहे किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी रफ्तार 5555 किमी प्रति घंटा है। यह मिसाइल सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों को 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को मार गिराने की क्षमता देती है।

पूर्व विस अध्यक्ष की मौत की जांच करे सीबीआइ : चंद्रबाबू नायडू

► **चंद्रबाबू बोले–यह खुदकशी और कुछ नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्या है**

► **देश के बुद्धिजीवियों को राज्य सरकार के रवैये पर बहस करनी चाहिए**

प्रदेश सरकार को राव की मौत से कोई लेना-देना नहीं : आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवतक गादिकोटा श्रीकांत रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि वाईएसआर सरकार का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव की मौत से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए राजनीतिक बदले के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। श्रीकांत रेड्डी ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने राज्य में गुटबाजी की राजनीति की, शुरुआत की। कोडेला भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके भ्रष्ट के व्यवहार के कारण बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष की मौत के बाद दक्षिण भारतीय राज्य में सियासी माहौल बहुत गर्मा गया है। सभी मुख्यमंत्री जगन के खिलाफ हमलावर हैं।

राष्ट्रपति भवन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी में एक और गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राष्ट्रपति भवन में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपित मोनू को गिरफ्तार किया है। मोनू उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। वह घटना के दौरान राष्ट्रपति भवन में ही अस्थायी तौर पर तैनात था। इससे पहले क्राइम ब्रांच राष्ट्रपति भवन में तैनात बलराम मोती व दिल्ली पुलिस के सिपाही हरेंद्र को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित मोती ने राष्ट्रपति भवन में तैनात सिपाही हरेंद्र, मोनू, वीरेंद्र और शेखर के सहयोग से दिल्ली व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के करीब 35-40 युवाओं से संपर्क साध उन्हें राष्ट्रपति भवन में चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए युवाओं से तीन से चार लाख रुपये तक लिया गए थे। वहीं कुछ युवाओं से बातचीत भी चल रही थी। लेकिन इससे पहले ही मोती दबोच लिया गया।

करीब डेढ़ साल पहले एक युवक ने बुलंदशहर व दूसरे ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था। मोनू व उसकी पत्नी बबीता को किसी प्लेसमेंट एजेंसी ने राष्ट्रपति भवन में नौकरी दिलवाई थी। जांच में सामने आया था कि युवाओं से लेनदेन की बात तय होने के बाद मोती ने अलग-अलग समूह में युवाओं के राष्ट्रपति भवन के परिसर में किसी कमरे में साक्षात्कार लिया था और परिसर में ही स्थित डिस्पेंसरी में मेडिकल कराया था। साक्षात्कार और मेडिकल के बावजूद तय समय पर युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। पुछताछ पर आरोपित आनाकानी करने लगे तो दो युवकों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

कुछ महीना पहले क्राइम ब्रांच ने पहले मोती और फिर सिपाही हरेंद्र को गिरफ्तार किया था। उनसे पुछताछ के बाद पिछले हफ्ते बुलंदशहर से मोनू को दबोच लिया। जांच में जिनकी सलिपत्ता पाई जा रही है। उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन से जुड़ा मामला होने के कारण क्राइम ब्रांच इसे बेहद गंभीरता से ले रही है।

गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। पहले इस आशय का शपथपत्र केवल एनजीओ के लिए आवेदन करने वाले को देना होता था।

विदेशी चंदा (नियमन) कानून में बदलाव के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के दौरान अपात स्थिति में इलाज की जरूरत होती है और वह किसी से विदेशी मदद प्राप्त करता है तो उसे एक माह के भीतर इस आशय की सूचना सरकार को देनी होगी। सूचना में मदद का स्त्रोत, भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य और किस तरह उसका इस्तेमाल किया गया, यह ब्यौरा देना होगा। पहले यह काम दो माह में करना जरूरी था। मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने को लेकर नियम-कायदों को सख्त बनाया है। इसके तहत एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 18000 एनजीओ के विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति समाप्त की गई है।

चीन–म्यांमार सीमा के पास उतरेंगे वायुसेना के विमान

गुवाहाटी, आइएनएस : अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास विजय नगर में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएनजी) का बुधवार को उद्घाटन किया जाएगा। यह एएलजी चंगलांग जिले के दुर्गम सर्किल में चीन और म्यांमार सीमा के समीप स्थित है। गुवाहाटी स्थित रक्षा पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल पी. खोंगसाई ने मंगलवार को कहा कि वायुसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल आरडी माथुर और पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान संयुक्त रूप से एएलजी का उद्घाटन करेंगे।

विजय नगर एएलजी का उद्घाटन अन्य सात एएलजी के शुरू होने के बाद किया जा रहा है। इससे पहले पासीघाट, मेचुका, वालोंग, तुतिंग, जियरे, अलोंग और तवांग में एएलजी के संचालन में लाया जा चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल खोंगसाई ने कहा कि विजय नगर में एएलजी के उद्घाटन के बाद एएन 32 सहित फिफ्स विंग विमानों का संचालन किया जा सकेगा। म्यांमार और चीन सीमा पर स्थित

बड़ा कदम

► **अरुणाचल में विजय नगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन आज**

► **पासीघाट, मेचुका, वालोंग, तुतिंग, जियरे, तवांग में एएलजी को हो रहा है संचालन**

होने के कारण विजय नगर एएलजी खास महत्व रखता है। सड़क नहीं होने से विजय नगर तक मोटर से नहीं पहुंचा जा सकता है। पूरी तरह कटे होने के कारण यह क्षेत्र दुर्गम माना जाता है। देखरेख के अभाव के कारण विजय नगर एएलजी 2016 से संचालन में नहीं था। डोकलाम विवाद के बाद केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में एएलजी को रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचलन में लाने की दिशा में कदम उठाया। अरुणाचल सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 2009 में एमओयू हुआ था। इसके तहत पासीघाट व अन्य एएलजी के बुनियादी ढांचा को विकसित करने का काम शुरू हुआ।

दैनिक जागरण

विनम्रता के बिना ज्ञान व्यर्थ है

कच्चे तेल का बाजार

सऊदी अरब के तेल टिकानों पर ईरान समर्थित हज़उती विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद कच्चे तेल के दामों में आया उछाल यही बताता है कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के बीच का टकराव किस तरह इस क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता है। हालाँकि सऊदी अरब की इस घोषणा के बाद कच्चे तेल के दामों की बढ़त थमती दिख रही है कि बहुत जल्द तेल का उत्पादन पहले की ही तरह होने लगेगा, लेकिन इसके बावजूद ईरान के खिलाफ अमेरिका के तीखे तैवर दुनिया को चिंतित करने वाले हैं। जहां सऊदी अरब को यह संदेह भर है कि हज़उती विद्रोहियों के ड़ोन हमले के पीछे ईरान का हाथ है वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह हमला ईरान की ही कार्रस्तीनी है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह ठीक नहीं कि अमेरिका ईरान की घेबेबंदी करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। हालाँकि ईरान के रुख-रूखे की सराहना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका ने उसके साथ की गई परमाणु संधि को जिस तरह रद्द किया उससे यही साबित हुआ कि सऊदी अरब को खुश करने के फेर में वह पश्चिम एशिया को संकट में डालने का भी काम कर सकता है।

अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसकी नीतियों से पश्चिम एशिया पहले ही तमाम मुश्किलों से घिर चुका है। इराक और फिर सीरिया की जो तबाही हुई उसके लिए एक बड़ी हद तक अमेरिका की मनमानी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। मुश्किल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना सोच-समझे कदम उठाने, उन्हें बीच में रोक देने या फिर पीछे हटने की अपनी आदत का परित्याग नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वह दुनिया के लिए संकट ही पैदा कर रहे हैं और वह भी ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं। चूँकि पश्चिम एशिया तेल बहुल क्षेत्र है इसलिए वहां जब भी अशांति उत्पन्न होती है वह दुनिया भर को प्रभावित करती है। सबसे अधिक प्रभावित होते हैं भारत सरीखे वे देश जो पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 83 फीसदी आयात करता है। कुछ समय पहले तक भारत इराक और सऊदी अरब के अलावा ईरान से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान पर पाबंदी लगाने के बाद भारत को न चाहते हुए भी उससे तेल खरीदना बंद करना पड़ा। भारत को अमेरिका के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उसकी ऊर्जा जरूरतों की परवाह करके ही अपने मित्रता धर्म का निर्वाह कर सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

उत्तरखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही सियासत भी गरमाने लगी है। चुनाव अगले महीने तीन चरणों में होने हैं। इसको देखते हुए खासकर सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। दोनों एक-दूसरे पर सियासी तीर छोड़कर चुनावी जमीन मजबूत बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख को छोड़कर बाकी पदों का चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा इन पदों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का सीधा चुनाव नहीं होता है, निर्वाचित सदस्यों के बीच से ही इन्हें चुना जाता है। ऐसे में बहुमत की सदस्य संख्या हासिल करने को लेकर राजनीतिक दल इन चुनावों में पूरी ताकत झोंके रहते हैं। राज्य में इन दिनों कहीं प्रत्याशियों का पैनाल तैयार हो रहा है तो कहीं चुनाव के लिए बाकी इंतजाम हो रहे हैं। अभी तक त्रिस्तरीय पंचायतों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भाजपा इसे तोड़ने का सपना बुन रही है। पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा अब उसकी मंशा इसमें और सुधार करते हुए पंचायतों को अपने फोल्ड में लेने की होगी। दूसरी तरफ अरसे से कांग्रेस पंचायतों से अपनी सियासी जमीन सीचती आई है, इसलिए वह भी पिछली गलतियों से समक लेकर नई रणनीति पर विचार करती दिख रही है। यह स्वाभाविक भी है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों की करारी हार की टीस उसके मन में कायम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इन दोनों दलों को छोड़कर सपा, बसपा और कई बार टूटन के बाद फिर से एक हुआ उक्रांद भी इन चुनावों में अपना वजूद तलाशने की जुगत में नजर आ रहा है। चुनावी रण में कौन किनना दमदार साबित होगा, यह तो जनता जनार्दन के फैसले पर निर्भर करेगा, पर एक बात सभी दलों को याद रखनी होगी कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, ना कि समाज में वैमनस्यता फैलाकर। हर चुनाव में इस तरह के कुत्सित प्रयास होते हैं, पंचायत चुनावों में इसकी आशंका ज्यादा बनी रहती है। अच्छी बात यह कि उत्तरखंड का मतदाता परिपक्वता दिखाता आया है। उसने ऐसे तत्वों को अपने मताधिकार से न केवल नाउमीप किया, यह संदेश देने की कोशिश भी की कि वे फिर से ऐसी हिमाकत नहीं करें। उम्मीद है कि मतदाता इन चुनावों में और अधिक परिपक्वता से अपने दायित्व निभाएंगे।

प्रभावहीन होती छात्र राजनीति !

आदर्श तिवारी

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजय प्राप्त हुई है। इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव का पद उसके खाते में गया तो कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआइ को महज एक सचिव पद से ही संतोष करना पड़ा। इस बार के छात्र संघ चुनाव को देखें तो यह चुनाव छात्र राजनीति में आ रही नीरसता की तरफ इंगित करता है। क्योंकि इस बार चुनाव में कौन जीता, कौन हारा, छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे क्या रहे, इसको लेकर आम जन तो दूर युवाओं ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। छात्रसंघ चुनावों में अब वह जोश नहीं दिखता जो 1970 से 2000 के बीच दिखता था। छात्र राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि समयानुसार छात्र राजनीति धीरे-धीरे सिकुड़ती गई और प्रभावहीन भी होती चली जा रही है। छात्र राजनीति से अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक पहुंचना बेहद कठिन हो गया है। इसके कारणों को देखें तो युवा छात्र नेताओं में निरंतरता और निष्ठा का अभाव है।

छात्रसंघ चुनावों में अब वह जोश नहीं दिखता जो 1970 से 2000 के बीच दिखता था ।इस पर गंभीरता से विचार करना होगा

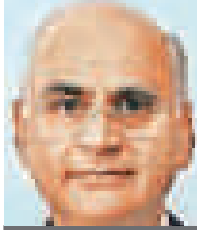
आज जानबूझकर ऐसे विमर्श खड़े किए जा रहे हैं जिससे मूल मुद्दे गौण हो जाते हैं और अनर्गल मुद्दों को तवज्जो मिलने लगती है। अमर्यादित होती छात्र राजनीति का सबसे जीवंत उदाहरण कभी जेएनयू तो कभी जाधवपुर विश्वविद्यालय में उठने वाले देश विरोधी नारे हैं। छात्र राजनीति के इस अवसान पर गंभीरता से विचार करना होगा तथा छात्रों को अपनी मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक आंदोलनों की तरफ लौटना होगा। छात्र राजनीति का स्वर्णिम युग अगर कहना हो तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि 1970 से 1985 का कालखंड छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम काल रहा और इसके नायक जयप्रकाश नारायण थे। आपातकाल के दौरान जेपी की एक छहरी के नीचे विभिन्न छात्र संगठन एकजुट होकर

आपातकाल के विरुद्ध जमकर लड़े और अपने उद्देश्य में सफल हुए। उस समय के छात्र नेताओं ने बहुत कम समय में ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बना ली और बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसे में गंभीर सवाल यही है कि आज छात्रसंघों की प्रासंगिकता क्या है? अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुए हैं। इनके परिणामों को लेकर पहले से अनुमान लगाए जा रहे थे। दरअसल इन दोनों विश्वविद्यालयों की वैचारिक बुनियाद ही परिणामों की तरफ इशारा कर देते हैं, पर डीयू में सावरकर की प्रतिमा को विरोध एवं एनएसयूआइ एवं वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति से की गई अभद्रता के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विजय ऐसी ओछी हरकतों को अंजाम देने वालों को कड़ा संदेश है। कांग्रेस सावरकर या उनके जैसे अन्य देशभक्तों को लेकर अपने पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों पर लगाम लगाए, क्योंकि आज का युवा वीर सावरकर के त्याग, बलिदान, राष्ट्रप्रेम को अपनी प्रेरणा मानता है। उनको अपमानित करने वाले इसके परिणाम से नहीं बच सकते।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जीएन वाजपेयी

मंदी से निपटने के लिए सरकार उन उद्योगों को उबारने पर ध्यान दे जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन या अन्य उद्योगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं



भारत ने 1947 में राजनीतिक आजादी हासिल की। इसके बावजूद करोड़ों भारतीय अभी भी आर्थिक उत्थान की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके सभी कार्यक्रम मसलन जनधन-आधार-मोबाइल, शौचालय, मुफ्त रसोई गैस और बिजली कनेक्शन, सबके लिए आवास, किसान सम्मान, मुद्रा, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा आवरण और पेंशन इत्यादि का लक्ष्य लोगों को गरीबी की जद से बाहर निकालना है। मुझे इन योजनाओं से जुड़ी कुछ बैठकों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। एक बार साउथ ब्लॉक के गलियारों में प्रधानमंत्री से बातचीत का अवसर भी मिला। वह गरीबी को खत्म करने के बारे में सोचते रहते हैं।

भारत में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। राजनीतिक इच्छाशक्ति का संबंध सत्तारूढ़ दल और उसके नेता की ताकत और प्रतिबद्धता से होता है। भारत का आर्थिक उत्थान 2014 और 2019 में में मोदी के चुनाव प्रचार अभियान के केंद्र में था। मतदाताओं ने भी पूर्ण बहुमत और मजबूत नेता के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। तमाम अर्थशास्त्री, टिप्पणीकार और विपक्षी नेता इस

लक्ष्य का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में जितनी सीटों का लक्ष्य रखा और उससे अधिक की प्राप्ति यही दर्शाती है कि 2024 तक उनका यह संकल्प भी पूरा हो सकता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि विविध पहलुओं पर निर्भर करती है। इनमें घरेलू और विदेशी, दोनों कारक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक सफलता दिलाने वाले कारकों से इनकी भूमिका एकदम अलग होती है। प्रबंधन का पहला सिद्धांत होता है कि कोई लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया है। फिलहाल देसी अर्थव्यवस्था घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर कुछ चुनौतियों से जूझ रही है। कुछ ढांचागत एवं चक्र्रीय पहलू भी उसकी यह में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अर्थव्यवस्था को ऊंची वृद्धि के दौर में दाखिला करना खासा जटिल काम है। इसमें सरकार को वैसा ही दृढ़ संकल्प दर्शाना होगा पहलुओं पर काम करने को समाप्त करने और अनुच्छेद 370 को हटाने में दिखाया।

मांग में सुस्ती और निवेश में ठहराव को दूर करने के लिए सरकार को कुछ साहसिक फैसले करने होंगे। इसके लिए ढांचागत सुधारों की शक्ति ही कुछ तात्कालिक कदम उठाने होंगे। ढांचागत सुधारों में भूमि एवं श्रम सुधारों के साथ ही सरकारी बैंकों के विनिवेश जैसे कुछ अनछूए पहलुओं पर काम करने को दखार होगी ताकि निवेश के गुणात्मक प्रभाव को बढ़ाया जा सके। उत्पादकता को बढ़ाना ही सभी ढांचागत सुधारों के मूल में होना चाहिए। उत्पादकता

इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि दारा शिकोह

बीते दिनों जब संघ के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल ने दारा शिकोह और औरंगजेब की तुलना की तो एक नई बहस छिड़ गई, परंतु यह बहस कितनी एकपंगी है इसका अनुमान तब लग जाएगा जब आज के युवाओं से पूछा जाए कि कितने लोग दारा शिकोह का नाम जानते हैं? शायद बहुत कम लोग ही यह बता पाएंगे। जब तक आप उच्च स्तर पर इतिहास विषय के रूप में न पढ़ें तब तक दारा शिकोह के बारे में जानकारी नहीं मिलती। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई और शाहजहां द्वारा नियुक्त संहसन का औपचारिक उत्तराधिकारी था। आज जिस गंगा-जमुनी तहजीब की बात बड़े जोर-शोर से की जाती है उसकी पहली लिखित प्रस्तुति दारा शिकोह की पुस्तक मंजुम-अल-बहरीन अर्थात दो समुद्रों का मिलन थी। यह एक मुगल शहजादे की ओर से हिंदू और इस्लाम के तालमेल पर पहला औपचारिक लिखित प्रयास था। लाहौर के प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर उसके गुरु थे तो काशी के विद्वान पंडित रात जगन्नाथ से उसने संस्कृत सीखी।

दारा शिकोह ने उपनिषदों का अध्ययन किया और उनका फारसी भाषा में ‘सिर्र-ए-अकबर’ नाम से अनुवाद कराया जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय शब्द। 17वीं शताब्दी में उपनिषदों के इसी फारसी अनुवाद से फ्रांसीसी अनुवाद हुआ, फिर लैटिन भाषा में और वहां से 19वीं शताब्दी में जर्मनी के आर्थर शापनहावर तक पहुंचा, जिन्होंने इसे ‘मानवीय ज्ञान की पराकाष्ठा’ कहा। फिर जर्मनी में वैदिक अध्ययन के प्रति 19वीं शताब्दी में दिलचस्पी उत्पन्न हुई। 20वीं शताब्दी के अनेक महान जर्मन वैज्ञानिकों आइंस्टीन, आर्टोहॉन और हाइजनबर्ग के विचारों पर वैदिक ज्ञान और दर्शन के प्रभाव के संकेत अनेक पुस्तकों में उपलब्ध हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा वेदों-उपनिषदों का अध्ययन जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सैद्धांतिक भौतिकी को सबसे बड़ी खोजें भी जर्मनी में ही हुईं। इसे महज संयोग मानना तर्कसंगत नहीं लगता।

दारा शिकोह भारत के मुसलमानों को जिस रास्ते पर ले जाना चाहता था वह ज्ञान-विज्ञान में कहां तक जा सकता था, यह समझा जा सकता है। शायद दारा शाहिकोह मुगल खानदान का इकलौता शहजादा था जिसने आध्यात्मिक विषयों का भी अध्ययन किया, जिसके नाम पर एक भी मंदिर तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि महान कहा जाने वाला अकबर भी ईश्वर आरोप से मुक्त नहीं



है। बरख्तियार खिलजी जैसों ने जहां नालंदा को विख्यात पुस्तकालय जलवाया तो दारा शिकोह ने पुस्तकालय बनवाया जो आज भी दिल्ली में मौजूद है। आप सोच सकते हैं कि यदि इस सोच का व्यक्ति बादशाह बना होता तो देश का भविष्य क्या होता? इसके उलट औरंगजेब ऐसा निर्मम शासक बना जिसने हिंदू मंदिरों के विध्वंस और सिख गुरुओं पर अत्याचार से नफरत की खाई को इतना चौड़ा कर दिया कि उसे पाटना आसान न हो सके। औरंगजेब में इस हद तक नफरत भरी थी कि उसने दारा शिकोह को बेड़ियों में जकड़कर पहले दिल्ली में घुमाया फिर तालेग खोफजदा हों, परंतु जब उसने देखा कि दिल्ली की जनता उसके प्रति सहनभूति प्रकट कर रही है तो उसने दारा का सिर कलम करकर अपने पिता शाहजहां को भिजवाया। उसने अपने बाकी दोनों भाइयों शुजा और मुराद की भी हत्या कराई। आप कह सकते हैं कि इतिहास में जो हुआ सो हुआ, आज इसका क्या संदर्भ है? चूंकि सेक्युलरिज्म के सूत्रा मुस्लिम समाज की राजनीती को औरंगजेब के रंग में रंगे रखना चाहते हैं इसलिए उसे कभी बाबर से भी नहीं जिन्ना से जोड़ते हैं। पराग्वे का मुख्य व्य्वसाय ही गो-पालन है। पूरे दक्षिण अमेरिका और अन्यत्र यहां से दुग्ध-उत्पाद निर्यात हो रहे हैं। वहां खेती-किसानी से आमदनी कुछ ही वर्षों में तीन-चार गुनी बढ़ गई है। वहीं गाय को लोग पूजते हैं। उनकी हत्या पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। ये सब बातें वैज्ञानिक सत्य हैं। वहां कोई रासायनिक कीटनाशक या यूरिया-अमोनिया का इस्तेमाल नहीं होता, जिन्हें लेखक अपरिहय मानते हैं। लेखक ने सुभाष पालेकर के विषय में एक भ्रांति फैलाने वाली बात यह लिखी है कि उनकी पद्धति में काली कपिला गाय का गोबर-गोमूत्र ही चलता है। मैंरे पास पालेकर का साहित्य है। मैंने उनके सेमिनार में भी शिरकर की है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा न लिखा



ही ऊंची जीडीपी वृद्धि को दिशा देती है। अपेक्षाकृत कमजोर निवेश के बावजूद यह कारगर होता है। कशधान सहित प्रत्येक नीतिगत मोर्चे पर स्पष्टता एवं निरंतरता भी सुनिश्चित करनी होगी। इनमें हमेशा अस्थिरता का भाव हावी रहता है। इस कड़ी को मजबूत करने से संस्थागत एवं विदेशी निवेशकों का भरोसा हासिल किया जा सकता है।

मौजूदा आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सरकार का पूरा जोर उन उद्योगों को उबारने के इदीर्गद केंद्रित होना चाहिए जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं या अन्य उद्योगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें कृषि, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, रत्न एवं आभूषण और वाहन जैसे तमाम अन्य क्षेत्र शामिल हैं। फिलहाल ये सभी क्षेत्र गंभीर की जकड़न में हैं। इन सभी के मर्ज के लिए इलाज की कोई एक ही पुड़िया नहीं है। मंदी के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक क्षेत्र की मदद के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। इन क्षेत्रों की वृद्धि से रोजगार के लाखों-लाख अवसर सृजित होंगे। इससे समग्र मांग में व्यापक रूप से इजाफा होगा। यह सीमेंट, इस्पात और

सेक्युलरिज्म के सियासी सूत्रमाओं ने अधिक किया है।

आज जो लोग भारत में मुसलमानों में प्रचारित डर और उनकी तमाम आशंकाओं का भयादोहन कर रहे है उन्हें मैं दूसरी धारा की याद दिलाना चाहता हूं। स्वतंत्र भारत में सेना का प्रथम वीरता पदक पाने वाले 1947 की नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। 115 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली शहमाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां थे और भारत की वैश्विक धमक का प्रथम उद्योगपति 1998 के पोखरण विस्फोट करने वाले मुख्य शिल्पी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन आखिर गंगा-जमुनी तहजीब के नाम पर छद्म धर्मपरिप्रेक्षता का झंडा उठाने वाले कितने नेता इन तीनों का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी इनके घर गए हैं?

ब्रिगेडियर उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। यहां आतंकवाद के आरोपियों के घर नेताओं की कतारें तो दिखीं, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। वीर अब्दुल हमीद के बलिदान की 50वीं जयंती 2015 में हुई थी। आखिर उसमें कितने सपाईं, बसपाईं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी नेता शामिल हुए? यद्यपि समुदाय के साथ संबद्ध करना इन सभी के महान व्यक्तित्व के साथ कुछ अन्याय है, परंतु डॉ. कलाम से बड़ा वैज्ञानिक पूरे आलम-ए-इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, मगर कितने लोग उनकी नमाज-ए-जानाजा में गए? यह वह धारा है जो दारा शिकोह, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, बुल्ले शाह और नसीर अकबराबादी से होते हुए, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, बिस्मिल्ला खां और डॉ. कलाम तक आती है, लेकिन सेक्युलरवादियों को इनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं पड़ता। यह सिर्फ देश और समाज का आज जरूरत है कि मुस्लिम समाज सेक्युलरिज्म के नाम पर थोपे गए औरंगजेब के रंग से बाहर निकले और दारा शिकोह की धारा के साथ जुड़े। राष्ट्रवाद और राष्ट्रप्रेम की धारा में उतर कर देखेंगे तो डर का स्याह रंग धुल जाएगा और आत्म गौरव की धारा की चमक स्वयं दिखेगी।

अभीर खुसरो का एक शेर है-‘खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। जो उतरा सो डूबि जा, जो डूबा सो पार।’ (लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

बढ़ जाता है।

अगर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि आठ प्रतिशत हो तो 15 प्रतिशत की सांकेतिक वृद्धि के आधार पर अनुमानित राजस्व प्राप्ति्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में परिसंपत्तियों को धुनाने की तत्काल जरूरत है। टुकड़ों में बिक्री या स्वाधित्व के मोर्चे पर बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। रणनीतिक विनिवेश की यह अपनानी होगी। सरकार को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए अपने खजाने का मुँह खोलना होगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि इस निवेश का असर तुरंत महसूस हो और मंदी पर काबू पाया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो राजकोषीय अनुशासन के मामले में कुछ छूट ली जा सकती है, लेकिन यह केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की शर्त पर ही होे। वैसे भी यह क्षेत्र शिहत से सुधार का ईंसाज कर रह है और इसमें अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से फायदा पहुंचाने की विपुल संभावनाएँ हैं। कारों की खरीद को प्रोत्साहन देने से पहले सरकार को सड़कें बनाने में निवेश करना चाहिए।

प्रधानमंत्री को संवाद स्थापित करने की कला में माहिर हासिल है। अपने इस कोशल का उपयोग उन्हें सभी क्षेत्रों के उद्यमियों और निवेशकों का प्रत्येक मोर्चे पर हाँसला बढ़ाने में करना होगा। उन्हें ‘आधुनिक भारत’ का सपना इस तबके के बीच लोकप्रिय बनाना होगा। इस साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री को यह माहश्वर करना होगा कि वास्तविक गलतियां और नुकसान स्वीकार्य होंगे और कानूनी ढंग से कमाई स्वागतयोग्य है। देश मोदी पर भरोसा करता है। निश्चित रूप से वह इन उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com



आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुषार्थ का तात्पर्य उन प्रयासों से है जिनके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। केवल मनुष्य को ही अपने कर्मों पर अधिकार है और इस अधिकार को यदि वह विवेक से प्रयोग करता है तो वह धर्म के मार्ग पर चलकर अमृत करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ धर्म का मतलब कर्मकांड या हिंदू मुस्लिम या ईसाई नहीं है, अपितु जिसके सिद्धांतों द्वारा मनुष्य समस्त प्राणी के कल्याण के द्वारा स्थायित्व तथा सम स्थिति को प्राप्त करता है। इस सम् स्थिति में वह परम चेतना से जुड़कर आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म का मार्ग नैतिकता तथा कल्याण का मार्ग है और इसी को स्वधर्म भी कहा जाता है।

धर्म के बाद अर्थ का स्थान आता है, परंतु साधारणतया अर्थ को सांसारिक सन-दौलत में जोड़कर देखा जाता है, बल्कि अर्थ से तात्पर्य है कर्मों द्वारा अर्जित आत्मिक उन्नति। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को इसको सबसे पहले करना चाहिए। अधिकार केवल कर्म पर है उसे फल की कामना नहीं करनी चाहिए और यह तभी संभव है जब कर्त्तव्य स्वार्थ, लोभ, मोह से रहित होकर कर्म करेगा। इस प्रकार कर्म करने से अर्जित आत्मसंतुष्टि तथा सकारात्मकता ही वास्तव में अर्थ है न कि धन, और यही सच्चा अर्थ है जिसके द्वारा वह संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ बढ़ता है।

सफलतापूर्वक कर्म की समाप्ति के बाद मनुष्य मन में फल के भोग की तरह-तरह की कामनाएं जागृत होती हैं जिन्हें साधारणतया कामवासना के रूप में देखा जाता है। इन कामनाओं को विवेकशिलि पुरुष आत्मकेंद्रित करता हुआ इन्हें शांत करता है, जिसके द्वारा उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है और वैराग्य प्राप्त होने के बाद ही ज्ञान प्राप्ति होती है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य स्वयं को पहचान कर परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करता है और इस प्रकार आसानी से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सच्चे अर्थों में धर्म, अर्थ एवं काम ही असली पुरुषार्थ है। आइए सच्चे पुरुषार्थ द्वारा जीवन को सफल करें।

कर्नल भगवान सिंह

मेलबाक्स

है, न ही बताया है। सब नस्लों की देशी गाय उन्हें स्वीकार्य हैं। मेरा अनुरोध है कि लेखक को सत्य-तथ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

अजय मित्तल, मेरठ

समझदारी से लेना होगा काम

यह पत्र ‘सऊदी तेल भंडारों पर हमले से कच्चा तेल हुआ महंगा’ के संदर्भ में है। आर्थिक मंदी, जीडीपी की घटती दरें कम नहीं थी कि अब इस खबर ने संकट को और गहरा दिया है। सऊदी अरब में हुई ड्रोन हमले की घटना से कच्चे तेल के दाम में तेजी आएगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 फीसद तेल आयात करता है। इससे तय है कि हमारा राजकोषीय घाटा और घटेगा, क्योंकि डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा। इस घटना का सीधा असर ज़रूरत की चीजों जैसे सज्जियों और फलों इत्यादि की कीमतों पर पड़ेगा। हमारी समस्या यहीं खत्म नहीं होती। हमें राजनयिक स्तर पर भी काम करना होगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बिगड़ते संबंध और अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान कि वह सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं, अच्छे संकेत नहीं हैं। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए की यह तीनों देश समझदारी से काम लेंगे और भारत भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएगा तो हम आने वाले किसी भी खतरे को टाल सकेंगे।

बाल गोविंद, नोएडा

विवादित बयान से बचें

देश के नेताओं को संवेदनशील और अति संवेदनशील

मुद्दों में फर्क करने और विवादित बयान न देने की कला सीखनी होगी। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नेता तो बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन देश में बेवजह का तनाव उत्पन्न हो जाता है। एक देश, एक विधान, एक झंडा और एक टेक्स तक तो ठीक है अब एक भाषा का मुद्दा कहां से आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि इससे बेवजह एक राजनीतिक हथियार विपक्ष को मिल जाएगा। आज देश में 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और अहिंदी भाषी राज्यों में भी लोग काम काज और संपर्क भाषा के लिए हिंदी सीख रहे हैं। संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। कितना अच्छा हो यदि उत्तर भारत में भी बांग्ला, उडिया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा पढ़ाई जाए, जिससे दक्षिणी भारतीय लोगों को अच्छा लगे वा वे भी खुद प्रेरित होकर वहां हिंदी को बढ़ावा देने लेंगे। जब हम उनकी भाषाओं को सम्मान देंगे तो वे खुद हिंदी के प्रति अपनी दुर्भावना खत्म कर देंगे। कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिए।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल- mailbox@jagran.com



अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस
ग्लोबल से संबद्ध

हमारे देश में एक आम नागरिक की जरूरतों का हवाला देते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का नारा बीते कई दशकों से दिया जाता रहा है। हाल तक आलम यह रहा है कि लोगों को सिर पर छत मुहैया करा देने को ही सरकार का सबसे बड़ा धर्म माना गया। खास तौर से उन शहरों के संदर्भ में जो रोजगार तो देते हैं, पर उनकी यह खूबी ही अब शहरों पर भारी पड़ने लगी है। लोगों की आवासीय दिक्कतों का हल देने के साथ-साथ भारी आबादी की जरूरतें पूरी करने का दबाव अब शहरों पर है, पर इसका नतीजा ऐसे अनियोजित शहरीकरण के रूप में निकला है, जिसने शहरों के पूरे माहौल को दमघोंटू बना दिया है। साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सहुूलियतों पर ऐसा अंतहीन दबाव पैदा कर दिया है जिसके सामने शहरों को स्मार्ट बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी पलीता लगात दिख रहा है। ऐसे में अब एक नया उपाय शहरी वेधशाला (अर्बन ऑब्जरवेटरी) जैसी तकनीक के रूप में सूझा है, जिसे हमारे देश में इस साल मार्च माह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस. पुरी ने लांच किया था।

शहरों की बदहाली : शहरी वेधशाला की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बात हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली उस ग्लोबल लिवेंबिलिटी इंडेक्स 2019 के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक लगती है जिसमें दुनिया के अच्छे शहरों की गणना का एक काम किया जाता है। पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पांच प्रमुख मानकों पर लोगों के निवास के उपयुक्त शहरों का आकलन करने वाले इस सूचकांक यानी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटीलिजेंस यूनिट (ईआइयू) जारी करती है। इसमें इस वर्ष भारत के चुनिंदा शहरों की स्थिति और बदतर होते हुए दर्ज की गई। जैसे-ईआइयू की ग्लोबल लिवेंबिलिटी इंडेक्स 2019 में दिल्ली पिछले साल के मुकाबले इस साल छह स्थान फिसलकर 118वें नंबर पर पहुंच गई। इस गिरावट के पीछे दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा अपराधों में बढ़ोतरी को अहम वजह माना गया। मुंबई दो पायदान नीचे गिरकर 119वें नंबर पर पहुंची और इसके लिए वहां पर्यावरण के अलावा सांस्कृतिक गिरावट को जिम्मेदार माना गया। दुनिया के 140 देशों के प्रमुख शहरों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका नीचे से तीसरे यानी 138वें और पाकिस्तान का कराची 136वें नंबर पर है। पर

ट्वीट-ट्वीट

एनआरसी का विरोध कोई भी हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। सरकार को इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। भारत ‘भारतीयों’ के लिए है, ‘घुसपैठियों’ के लिए नहीं।

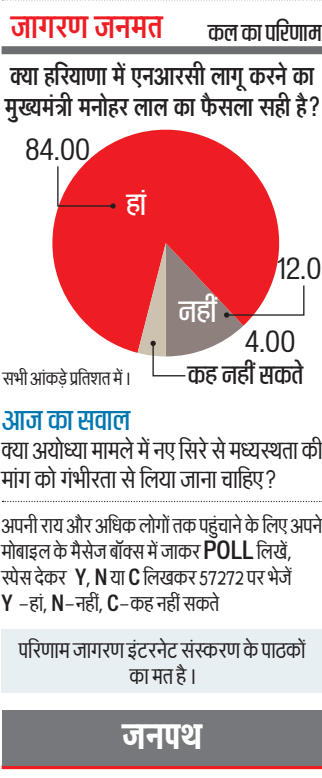
आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

यह साल विमानन कंपनियों के लिए दुःखान रहा। इंडिगो का लाभ 93 फीसद घट गया। स्पाइसजेट नुकसान में चली गई। महज 20 विमानों के बड़े के साथ संचालित होने वाली विस्तारा ने 800 करोड़ रुपये गंवा दिए। एयर इंडिया को 8,500 करोड़ रुपये का भारी -भरकम घाटा हुआ और जेट एयरवेज इतिहास में दफन हो गई।

तरुण शुक्ला@shukla_tarun

प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा बांध का दौरा कर अपना 69वां जन्मदिन मनाया। यह बांध श्री जीर्जेंस डैम की तुलना में बहुत ही छोटा है। जहां चीन ने अपने भीमकाय बांध का निर्माण तय समयसीमा से पहले कर लिया वहीं भारत में कुछ एनजीओ की ‘मेहरबानी’ से दशकों तक नर्मदा बांध का काम पूरा ही नहीं हो पाया।

ब्रह्मा वेणीनी@Chellaney



रोटी हिंदी फिल्म की खाकर हुए महान, लगा उपजने आजकल कमल हसन को ज्ञान। कमल हसन को ज्ञान सियासत जरूरी सुझी, बड़ी चार सौ बीस लगे चाची अनुरूपी। हिंदी को जो लोग समझते कमतर -छोटी, दिन-प्रतिदिन है खाय रहे उसकी ही रोटी।

- ओमप्रकाश तिवारी

करोड़ भारतीय शहरों के बाशिंदे बन चुके थे साल 2008 में और उम्मीद है कि 2030 तक यह तादाद बढ़कर 59 करोड़ पहुंच जाएगी।

अनियोजित शहरीकरण का हो कारगर इलाज

आज देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने का दबाव हमारे शहरों पर है, पर इसका नतीजा ऐसे अनियोजित शहरीकरण के रूप में निकला है, जिसने शहरों के पूरे माहौल को दमघोंटू बना दिया है। साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सहुूलियतों पर ऐसा अंतहीन दबाव पैदा कर दिया है जिसके सामने शहरों को स्मार्ट बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी पलीता लगात दिख रहा है। ऐसे में अब एक नया उपाय शहरी वेधशाला (अर्बन ऑब्जरवेटरी) जैसी तकनीक के रूप में सूझा है, जिसे देश में इस साल मार्च माह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस. पुरी ने लांच किया था

पड़ोसी से आगे रहना हमारे लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय शहर दुनिया के दर्जनों शहरों के आगे बेहद फीके हैं। दुनिया के 140 देशों की इस सूची में ऑस्ट्रिया का वियना अव्वल आया है और टॉप के 10 शहरों में कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के तीन-तीन शहर शामिल हैं। ईआइयू की सूची का मकसद दुनिया को यह बताना है कि शहरीकरण का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वहां बड़ी आबादी के रहने के प्रबंध कर दिए जाएं और एक बार लंबा-चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, बल्कि इसका संदेश यह है कि शहरीकरण योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और उसमें शहरी आबादी को कामकाज की सुविधा के अलावा जिंदगी की कई जरूरी सुविधाएं आबादी से मुहैया हों। साथ ही ये शहर प्रदूषण मुक्त हों और सुरक्षा एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को दें।

आबादी का बढ़ता बोझ : शहर कैसे भी क्यों न हों उनकी जरूरत से अब इन्कार नहीं किया जा सकता। गांव-कस्बों में रोजगार की कमी और बढ़ती आबादी के बरक्स खेन-खलिखनों का घटना आकार बीते कई दशकों से लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। यह पलायन रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब रोजगार के साथ शहरीकरण देश के विकास की पहली जरूरत है। देश में एक नया मध्यमर्ग उन्हीं लोगों के बीच से उभर रहा है जो ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर बेहतर जीवनशैली वाले जीवन की इच्छा के साथ पलायन कर रहे हैं। साल 2008 में 34 करोड़ भारतीय शहरों के बाशिंदे बन चुके थे और उम्मीद है कि 2030 तक यह तादाद बढ़कर 59 करोड़ पहुंच जाएगी, पर इतने लोग रहेंगे कहां? क्या उन्हीं शहरों में जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के बोझ के कारण पहले से ही कराह रहा है और जहां रहने के लिए पर खरीदना आम आदमी के पहुंच के बाहर की चीज हो गई है या

फिर वहां जहां नए सपनों की नींव रखी जानी है। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार देश में सी स्मार्ट शहर बनाने की योजना के रूप में हमारे सामने रख चुकी है, जिस पर काम चल भी रहा है। हालांकि इन सौ शहरों को जैसे-तैसे कुछ स्मार्ट बना लिया जाए तो भी अहम सवाल यह है कि देश के उन सैकड़ों शहरों का क्या होगा, जहां का अनियंत्रित और अनियोजित विकास गंभीर मज बन चुका है और उससे निजात पाने की कोई योजना या पेशकश किसी भी कोने से होते हुए दिखाई-सुनाई नहीं पड़ रही है।

ढाँचागत खामों : ध्यान रहे कि लंबे समय तक गांवों का मुलुक कहलाने वाले भारत में शहरीकरण एक ऐतिहासिक बदलाव है। असल में आबादी के परिप्रेक्ष्य में अब जितने भी परिवर्तन होने हैं, उनका सीधा असर हमारे शहरों की दशा-दिशा पर पड़ेगा। खास तौर से उन शहरों पर, जिनकी सूरत अभी कुछ ठीक नहीं है। समस्या यह है कि विकसित देशों की देखादेखी हमने शहरीकरण को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इस तब्दीली का हमारी सरकारों और योजनाकारों ने कोई गंभीर नोटिस नहीं लिया। नतीजा यह निकला है कि आज देश के ज्यादातर शहर बेकायू और अनियोजित फैलाव के शिकार हो गए हैं। रोजी-रोटी के बेशुमार मौके देने के लिहाज से ये बेरोजगारों के स्वर्ग करते जाते हैं, पर अनियंत्रित शहरीकरण ने इन्हें असल में कहीं का नहीं छोड़ा है। स्मार्टनेस का सपना देख रहे इन सारे शहरों की पहली मौलिक समस्या हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी है। सड़कें, सीवर, बिजली, पानी की मूलभूत कमियां के बाद अवैध कब्जों और बिना किसी नियोजन के विकास ने ऐसे ज्यादातर शहरों को नर्क जैसी स्थितियों का हाल यह है कि वे जहरीले बाद सामाजिक परिवेश और कानून व्यवस्था जैसे सवाल हैं, जो इन ज्यादातर शहरों में बड़ी समस्या बनकर सामने आए हैं। यह सिर्फ एक

शहरी वेधशाला से बदलेगी सूरत

अवधारणा के तौर पर शहरी वेधशाला का विचार सबसे पहले वर्ष 2997 में इस्तांबुल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट-2 सम्मेलन में पेश किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला डाटा (सूचनाओं), चित्रों और वीडियो के जरिये शहरी संसाधनों पर पड़ रहे दबावों का स्टीक आकलन हो सकता है और कैसे इन आंकड़ों, चित्रों और वीडियो आदि का विश्लेषण एक वीडियो वॉल बनाकर किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से लगातार जुटाए जाने वाले डाटा को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि शहर के किस

हिस्से में विकास के मदेनजर क्या अभाव पैदा हो गया है और कहां किस चीज की तत्काल प्रबंधन, प्रदूषण, परिवहन, शिक्षा और जटिल होती जा रही चुनौतियों से निपटने में क्या रणनीति बनानी चाहिए और क्या नीतिगत फैसले लेने चाहिए, शहरी वेधशाला से मिले विश्लेषण के नतीजे योजनाकारों की इसमें भी मदद कर सकते हैं।

खास यह है कि इस वेधशाला के तात्कालिक और पूर्व में लिए गए संरक्षित आंकड़े एक तुलनात्मक अध्ययन में सहायक साबित होते हैं और इससे समुचित शहरीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकताएं फौरन तय की जा

सकती हैं, बशर्ते सरकारों और योजनाकार उन्हें लागू करने में कोई देरी न करें। कचरा प्रबंधन, प्रदूषण, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े जब शहरी वेधशाला की मदद से किसी वीडियो वॉल पर तत्काल देखें जा सकेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि अनियोजित शहरी विकास की दशा और दिशा सुधारने के काम में भी तेजी आ सकेगी। ध्यान रहे कि भविष्य में गवर्नेस का ज्यादातर काम डाटा-आधारित (डाटा-ड्रिवेन) होगा, ऐसे में अर्बन ऑब्जरवेटरी शहरीकरण की समस्या का एक उचित समाधान देते हुए प्रतीत हो रही है।

विडंबना नहीं है कि आज महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, दहेज हत्या, दुष्कर्म, बच्चों की सुरक्षा आदि के मामले में शहरों का ही रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। अवैध निर्माण और जल-वायु और जमीनी प्रदूषण तो देश की राजधानी दिल्ली तक में बेइतहह है, बाकी शहरों के बारे में क्या कह जाए।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव : यह अनियोजित विकास का ही नतीजा है कि आज हमारे शहरों में बसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाओं से महरूम है। कारोबार, औद्योगिकीकरण, उपभोक्तावाद तथा जीवन के प्रति लोगों के बदलते नजरिये के कारण ज्यादातर शहरों का हाल यह है कि वे जहरीले और मरते हुए शहरों में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में सफल यह है कि अगले 15 वर्षों में लाखों की जो आबादी शहरों की छाती पर काबिज

होने वाली है, क्या उसके रहन-सहन की प्रबंध की कोई ऐसी योजना हमारी सरकारों के पास है जिससे न सिर्फ इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकें, बल्कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और हवा-पानी पर इस दबाव का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। सच्चाई यह है कि बीते 15-20 वर्षों में आबादी के बोझ तले दब रहे इन शहरों के नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव बना हुआ है। ऐसे में शहरों की दशा सुधारने वाली योजनाओं की सफलता भी लगातार संदिग्ध बनी हुई है।

आमजन की भूमिका : असल में शहरों को स्मार्ट बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकारों पर छोड़ने का ही खामियाजा है जो हमारे शहर आज भुगत रहे हैं। शहरों में रह रहे लोगों और वहां बसने के लिए आने वाली आबादी ने अगर कभी इसकी फिक्र की होती कि पूजास्थल वहां की सड़कों के रास्ते में अड़चन न बनें, अवैध कब्जों

कथित विशेषज्ञों को चौंका रहे आम कश्मीरी



आतंकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद लोगों का आतंकियों और अलगाववादियों के फरमान को न-फरमाना बनाना बात देना है कि अपने कारोबार शुरू करने, मॉडियों में अपनी फसल पहुंचाते हुए

बदलाव को अपनी सहमति देते हुए कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि देर आयद दुरुस्त आबद। आम लोगों की मनोभावना और उनकी चाह का इससे बड़ा सुबुत क्या होगा कि कश्मीर में किसी भी जगह केंद्र सरकार के फैसले के

खिलाफ कोई बड़ी जनাক्रोश रैली नहीं नहीं हुई है। उल्टे सेना की भर्ती रैलियों में नौजवानों की भीड़ बड़ रही है, नैफेड द्वारा लगाई जा रही मॉडियों में किसान सेब लेकर आ रहे हैं। पुलिस के पास जाकर लोग अपने-अपने इलाकों में

अलगाववादियों के जबरन बंद से आजादी की मांग कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने पर कश्मीर में तिरंगा धामने वाले हर हाथ के गायब होने की धमकी देने वाली पीपीडी अध्यक्ष भाबूबा मुप्ती का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वह बीते डेढ़ माह से कहां है, किस हाल में हैं, उनके परिजनों के अलावा कोई नहीं जानना चाहता। स्व शासन को कश्मीर मसले का एकमात्र हल बताने वाले नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा अभिनियम के तहत बंदी बनाए जाने पर भी आम कश्मीरियों में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

अलगाववादी सैय्यद अली शाह गिलानी और उनकी मंडली क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। मतलब साफ है कि आम कश्मीरी दिल्ली से जिस राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय चाहता था, वह उसने देरुल ली है। वादी के हालात बतलाते हैं कि आम कश्मीरी मानो बीते 70 साल से इसी दसा का इंतजार कर रहा था।

बाल्टिस्तान का रास्ता साफ कर दिया था। 29 अगस्त, 2009 को 'गिलगित-बाल्टिस्तान अधिकारिता एवं स्व प्रशासन अध्यादेश' पाक मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था। उस अध्यादेश पर पाक राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। अध्यादेश के हवाले से गिलगित-बाल्टिस्तान को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो गया था। उस समय इस कदम की आलोचना भारत के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने भी की थी। दूसरी ओर, 'गिलगित-बाल्टिस्तान संयुक्त आंदोलन' ने इसे खारिज करते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, जिसे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार प्राप्त हो। मतलब यदि भारत 370 को निरस्त करते हुए लदाख और जम्मू-कश्मीर की शासन राजनीतिक इतिहास में संसद द्वारा बदलाव करता है तो पाकिस्तान की निहाह में गलत है। फिर उसने उम्माद को दावत नहीं देना चाहते, जिस कारण उनकी कुर्सी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। हालांकि बाहरी दुनिया को वे बताए रखना चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर सभी दल-जमात एक हैं। इसमें जो बात सबसे अधिक अखरती है, वह ये कि भारतीय इंटीलिजेंस और उसकी रणनीति पीओके की अंदरूनी राजनीति को भेद पाने में अब तक असफल रही है। हमने उनके मतभेदों का फायदा नहीं उठाया है। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांट रखा है। एक है, 'पीओके', और दूसरा है गिलगित-बाल्टिस्तान। ' पीओके' या 'गुलाम कश्मीर' की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान ने बहुत पहले से चीन के वास्ते गिलगित-

बाल्टिस्तान का रास्ता साफ कर दिया था। 29 अगस्त, 2009 को 'गिलगित-बाल्टिस्तान अधिकारिता एवं स्व प्रशासन अध्यादेश' पाक मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था। उस अध्यादेश पर पाक राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। अध्यादेश के हवाले से गिलगित-बाल्टिस्तान को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो गया था। उस समय इस कदम की आलोचना भारत के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने भी की थी। दूसरी ओर, 'गिलगित-बाल्टिस्तान संयुक्त आंदोलन' ने इसे खारिज करते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, जिसे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार प्राप्त हो। मतलब यदि भारत 370 को निरस्त करते हुए लदाख और जम्मू-कश्मीर की शासन राजनीतिक इतिहास में संसद द्वारा बदलाव करता है तो पाकिस्तान की निहाह में गलत है। फिर उसने उम्माद को दावत नहीं देना चाहते, जिस कारण उनकी कुर्सी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। हालांकि बाहरी दुनिया को वे बताए रखना चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर सभी दल-जमात एक हैं। इसमें जो बात सबसे अधिक अखरती है, वह ये कि भारतीय इंटीलिजेंस और उसकी रणनीति पीओके की अंदरूनी राजनीति को भेद पाने में अब तक असफल रही है। हमने उनके मतभेदों का फायदा नहीं उठाया है। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांट रखा है। एक है, 'पीओके', और दूसरा है गिलगित-बाल्टिस्तान। ' पीओके' या 'गुलाम कश्मीर' की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान ने बहुत पहले से चीन के वास्ते गिलगित-

घरों में होने वाला वायु प्रदूषण बढ़ा रहा हृदय रोग का खतरा

जेएनएन, नई दिल्ली : एक नए अध्ययन में बताया गया है कि हृदय की बढ़ती बीमारियों का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। अध्ययन में दो रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक आम बीमारियों और उनसे होने वाली मौतों के बारे में है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 21 देशों में वयस्क लोगों में होने वाली हृदय की बीमारियों के संबंध में है।

इस रिपोर्ट के भारत के लिए व्पा है मायने : अध्ययन में बताया गया कि घरों में होने वाला वायु प्रदूषण भारत में हृदय रोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह खतरा मधुमेह, तंबाकू के सेवन, कम शारीरिक गतिविधि और खराब आहार से होने वाले खतरे से भी ज्यादा है। हृदय रोग के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान के लिए शोधकर्ताओं ने जनवरी 2005 और दिसंबर 2016 के बीच 1,55,722 प्रतिभागियों को अपने अध्ययन में शामिल किया। इसमें भारत सहित पांच निम्न आय वाले देशों के 35,793 प्रतिभागी शामिल थे। पीयूआरई ने अपने अध्ययन में बताया कि 21 देशों में हुए अध्ययन में भारतीयों का फेफड़ा सबसे कमजोर पाया गया। ग्रामीण भारत में कम से कम 65 फीसद घरों में खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिससे वे वायु प्रदूषण की चपेट में आते हैं। वहीं, अगर शहरी इलाकों में देखें तो लोगों को मच्छर मारने वाली कॉइल के धुएं आदि से भी दिक्कतें होती हैं।

मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक और इस अध्ययन के सह लेखक डॉ. वी मोहन के मुताबिक, निम्न आय वाले देशों में घरेलू वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर इस वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पा सके तो हृदय रोग से होने वाली मौतों में अभूतपूर्व कमी लाई जा सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, अभी तक के अध्ययनों में वायु प्रदूषण फैलाने के रूप में सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां आदि को ही चिह्नित किया गया था, लेकिन घर में होने वाले वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया। नए अध्ययन से सामने आया है कि अगर इस ओर कमी लाई जा सके तो काफी हद तक हम हृदय रोग की बीमारियों को रोक सकते हैं।



निम्न आय वाले देशों में हृदय रोग के लिए 10 बड़े खतरे

कारण	प्रतिशत में
उच्च रक्त वाप	14.3
हाई नान-एचडीएल कोलेस्ट्रॉल	14.2
घरेलू वायु प्रदूषण	12.0
डायबिटीज	10.4
कमजोर आहार	10.0
मोटापा	7.0
शिक्षा की कमी	6.0
तंबाकू	4.5
कम शारिरिक गतिविधि	2.2
अधिक शराब का सेवन	2.0

निम्न आय वाले देशों में मौत के दस बड़े खतरे

कारण	प्रतिशत
कमजोर आहार	19.2
शिक्षा की कमी	13.7
मांसपेशियों की कमजोरी	10.9
घरेलू वायु प्रदूषण	9
तंबाकू	7.6
डायबिटीज	6.7
उच्च रक्तचाप	5.6
कम शारिरिक गतिविधि	2.7
अवसाद	1.9
अधिक शराब का सेवन	1.8

हृदय रोग और कैंसर

अध्ययन की दूसरी रिपोर्ट में 21 देशों के 1,62,534 लोगों पर अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया कि हृदय रोग वैश्विक स्तर पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु दर का प्रमुख कारण बना हुआ है, लेकिन उच्च आय वाले देशों में ऐसा नहीं है। यहां पर होने वाली मौतों के लिए कैंसर हृदय रोग से दोगुना जिम्मेदार है। यह अनुमान लगाया गया था कि 2017 में दुनिया में 5.5 करोड़ मौतें हुई थीं, जिसमें से करीब 1.77 करोड़ लोगों की मौत हृदय रोग की वजह से हुई थी।

फोटो न्यूज



पॉलीथिन पर प्रतिबंध की तैयारी से हैंडलूम व्यवसाय को मिली संजीवनी

ओम बाजपेयी, मेरठ

देश में दो अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती से प्लास्टिक बैग, कप समेत छह प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2022 तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध की तैयारी हैंडलूम व्यापार के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इसके चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कपड़े की विशेष पोर्टली (कपड़े का थैला) में प्रसाद वितरित करने की योजना बनाई है। इससे जहां रोजगार बढ़ेगा, वहीं देश में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के टेंडर में ढाई लाख थैले हर माह सप्लाई करने की बात कही गई है, पर इससे खाली बैठे श्रमिकों को प्रदेश के मेरठ की बीआइ इंडस्ट्रीज के सैंपल को बोर्ड के समक्ष रखा है। 10 गुणा 12 साइज के इस थैले की चौड़ाई तीन इंच होगी। बीआइ इंडस्ट्रीज के मालिक नीलकमल रस्तोगी ने बताया कि पहले 40 से 50 हजार थैले प्रतिमाह सप्लाई पर बात चल रही है। इन थैलों में काम पूरी तरह हथ का है, जिसमें समय और मेहनत



मेरठ में बने कपड़े के थैले। सबसे बाएं श्राइन बोर्ड के लिए बनाया गया सैंपल।

दोनों ज्यादा लगते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के चलते रेट कम है, पर इससे खाली बैठे श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। महिलाओं को प्रशिक्षित कर प्रति पीस रेट पर थैलों की सिलाई कराई जाएगी।

दक्षिण के राज्यों ने दिखाई राह : जब छह माह पहले पॉलीथिन के थैलों पर सख्त पाबंदी की बात उठी तो दक्षिण भारत के राज्यों ने पहले पहल की। तमिलनाडु सरकार की कंपनी को-

ऑप्टेक्स टेक्स हैंडलूम परिधानों और बेड लिनेन की बिक्री से जुड़ी है। कंपनी ने जनवरी-फरवरी में कपड़े के थैलों की सप्लाई के लिए ई टेंडर जारी किया था। मेरठ के बीआइ इंडस्ट्रीज के नीलकमल ने अपने सहयोगी के साथ आवेदन कर दिया। उसके बाद से मेरठ में बने दो लाख से अधिक थैले चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में ग्राहक थाम चुके हैं।

फीसद तक तनाव और थकान को कम किया जा सकता है ऑफिस में एक मिनट तक प्रकृति से जुड़ी पैटिंग को देखकर। एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है।

स्वच्छता की लड़खड़ाती त्‍यवस्‍था के लिए बैसाखी बने पेशेवर संभाली कमान

जीएम रुपाली बेरी और बिजनेसमैन देव डावर ने साथियों संग बनाया एनजीओ

राजेश भट्ट, लुधियाना

पंजाब के लुधियाना की सड़कें हों या फिर पार्क, सरकारी दफ्तर हों या सार्वजनिक स्थल, हर जगह गंदगी ही गंदगी। इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी कई बार फटकार लगाई। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम से 50 लाख रुपये बैंक गारंटी जमा करवाने को कह चुका है। ऐसे में जब सरकारी तंत्र फेल हुआ तो शहर के कुछ पेशेवर इस व्यवस्था के लिए बैसाखी बनकर आगे आए और शहर की सफाई में जुट गए। यह लोग रविवार सुबह शहर के एक हिस्से का चयन करते हैं और वहां सफाई में जुट जाते हैं।

खास बात यह है कि ये युवा खुद सफाई करने के साथ स्थानीय लोगों और स्कूल के विद्यार्थियों को भी प्रेरित कर अपने साथ जोड़ लेते हैं। साफ सुथरे शहरों की बात करें तो लुधियाना देश के

बाघ और वन बचाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करेगा एनटीसीए

त्रिलोक रावत, रामनगर

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) बाघ सुरक्षा व वन संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले वन विभाग के फील्ड कर्मियों को पुरस्कृत करने की योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत एनटीसीए देश भर के टाइगर रिजर्व व वन प्रभागों से चयनित वन दरोगा, वन रक्षक व वॉचर को हर साल एक-एक लाख की इनामी राशि देगा।

देश में बाघों के संरक्षण के लिए वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। टाइगर रिजर्व के बाहर वन प्रभागों में भी बाघों की अच्छी खासी मौजूदगी है। बाघ व अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा फील्ड स्टाफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही स्टाफ वन्य जीवों की सुरक्षा में वास्तविक चुनौतियों का सामना भी करता है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंसक वन्य जीवों के अलावा शिकारियों व वनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के निशाने पर भी फील्ड स्टाफ रहता है। अब एनटीसीए दिल्ली

को ने तय किया है कि फील्ड स्टाफ को न केवल

फील्डकर्मों खुद भी कर सकेंगे अपना नामांकन

मानको पर खरे उतरने वाले फील्डकर्मों खुद भी अपना नामांकन करा सकता है। इसके अलावा रेंज ऑफिसर के द्वारा भी यह आवेदन दिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर रिजर्व के निदेशक या डीएफओ द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को यह नामांकन भेजा जाएगा। जहां से यह एनटीसीए को भेजा जाएगा। नवंबर तक सभी राज्यों ने यह नामांकन देने है। इस संबंध में एनसीटीए की ओर से आदेश भी जारी हो गए हैं।



आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाए, बल्कि उनके बाघ सुरक्षा व वन संरक्षण के कर्माों को पहचान भी दी जाए।

इन मानकों पर उतरना होगा खरा

वन्य जीव सुरक्षा व शिकार के रोकथाम की गतिविधि में योगदान

वन्य जीवों के वासस्थलों के प्रबंधन में भूमिका

वन्य जीव अपराधों की खोज, जांच व अभियुक्तों की गिरफ्तारी में योगदान

वन्य जीवों की निगरानी में योगदान

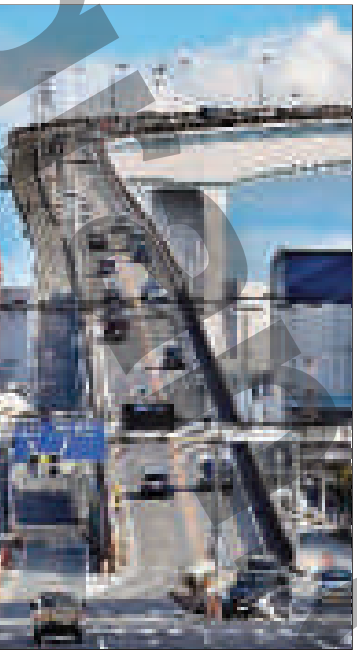
गांव के पुनर्वास के कार्य में योगदान

लोगों की भागीदारी व पर्यावरणीय विकास में योगदान

पर्यटन प्रबंधन व अनुपालन कराना

फील्ड स्टाफ के काम को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। उन्हें पहचान देने के लिए के लिए यह अवार्ड घोषित किया है। दैनिक श्रमिक भी घर से दूर रहते हैं, उनका वेतन कम होता है। वे बाघ संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें, इसके लिए उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देशभर के टाइगर रिजर्व व वन प्रभागों में से दो वन दरोगा, दो वन रक्षक व दो वॉचर को यह पुरस्कार दिया जाना है।

— सुरेंद्र महरा, डिट्टी इंस्पेक्टर जनरल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)



नो पॉलीथिन और सेव ग्राउंड वाटर मुहिम भी करेंगे शुरू

देव डावर ने बताया कि उनकी संस्था का फोकस अब नो पॉलीथिन ड्राइव पर है। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन की वजह से ही कूड़ा प्रबंधन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस वजह से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। इसके अलावा गिरते भूजल को बचाने के लिए भी मुहिम शुरू की जाएगी। उनकी संस्था के साथ भारतीय विद्या मंदिर और अरविंदों कॉलेज के विद्यार्थी भी जुड़ चुके हैं।

फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को साथ जोड़ा और फिर काम में जुट गए।

अपने स्तर पर फंड एकत्रित करते हैं सदस्य : रुपाली ने बताया कि संस्था के सदस्य ही अपने स्तर पर फंड एकत्रित करते हैं और सफाई मुहिम पर खर्च करते हैं। खास बात है कि इस संस्था में कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं है। संस्था की

कोर कमेटी है, जिसमें रुपाली, देव, कुणाल, आशु, विजय, तरविंदर, हिमांशु और प्रशांत शामिल हैं।

ऐसे हुई संस्था की शुरुआत: रुपाली बेरी बताती हैं कि उनके और देव डावर के मन में समाज सेवा करने की इच्छा लंबे समय से थी। उनकी इस संबंध में कई बार आपस में बात

कमाल की काव्या, एक ही समय में दोनों हाथों से लिखती हैं सीधा-उल्टा

मो. इम्तियाज अंसारी, रायपुर

प्रतिभा को परिचय के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वह अपनी पहचान खुद कर देती है। ऐसी ही प्रतिभा की धनी हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की 12 साल की काव्या चावड़। वह एक ही समय में दोनों हाथों से लिखने की काबिलियत रखती हैं। खास बात यह है कि एक हाथ से सीधा तो दूसरे हाथ से उल्टा लिखती हैं। उल्टे लिखे अक्षरों को आईने से देखने पर वे सीधे दिखाई देते हैं।

काव्या रायपुर के हेली हार्ट स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा हैं। उनको उनकी इस प्रतिभा के लिए लेडी वायरस कहा जाने लगा है, क्योंकि उन्हें यह प्रेरणा श्री इंडियट्स फिल्म से मिली, जिसमें लोकप्रिय किटदार वायरस (वीरु सहस्त्रबुद्धि) दोनों हाथ से लिखते थे। उन्हीं को देखकर काव्या ने भी ऐसा करने की शुरुआत की और धीरे-धीरे दक्ष हो गई।

काव्य बताती हैं, 'चार साल पहले श्री इंडियट्स फिल्म देखी थी। तभी वायरस को देखकर आइडिया आया कि जब यह दोनों हाथ से लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं? तभी से मैंने इस तरह लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। आज अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्दों को फर्फटे के साथ दोनों हाथों से लिख सकती हूं।' अभी काव्या गुजराती भी सीख रही हैं। उनके पिता प्रीतेश चावड़ा और माता नेहा चावड़ा का कहना है कि काव्या की यह प्रतिभा हम लोगों को भी पता नहीं थी, लेकिन यह हमेशा बोर्ड पर ऐसे ही लिखती रहती थी। जब इसके बारे में पता चला तो बहुत अच्छा लगा। पिता प्रीतेश कहते हैं, 'काव्या पिछले तीन-चार साल से लिख रही है, लेकिन हम लोगों को छह महीने पहले पता चला। बेटी को इसके लिए हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं।'

टीवी देखने के साथ लिखने का भी करती हैं अभ्यास : अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए काव्या हर दिन स्कूल से आने और घर में होमवर्क पूरा करने के बाद एक घंटे से अधिक इस तरह से लिखने का रियाज करती हैं। साथ ही जब घर वाले बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तो काव्या टीवी देखने के साथ लिखने का भी अभ्यास करती हैं।

हुई। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में काम करने पर विचार किया। बाद में फैसला किया गया कि उनकी संस्था शहर को साफ-सुथरा और हरा-भरा बनाने के लिए काम करेगी। इस बरसात के सीजन में 850 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। इनकी देखभाल के लिए दो माली नियुक्त भी किए हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार 28 अप्रैल, 2019 को सफाई मुहिम शुरू की तो सिर्फ छह लोग थे। इनमें वह दोनों खुद और प्रतीक, पारस, डॉ. सिमरन और किक्मी शामिल थे। आज उनकी टीम में 100 लोग हैं। वहीं, सोशल मीडिया के जरिये भी शहर के लोगों को जोड़ रहे हैं।

पार्क और सड़क के किनारे करते हैं सफाई : रुपाली बेरी का कहना है कि किसी भी शहर में सफाई का आकलन उस शहर की सड़कों और पार्कों के आधार पर किया जाता है, इसलिए उनकी संस्था ने सड़क के किनारों और पार्कों में सफाई करने पर फोकस किया है। उन्होंने बताया कि पहले तो वह कूड़ा एकत्रित करते हैं और फिर खुद अपने स्कूटर, कार में निगम के ड्रों तक गिराने जाते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news



श्री इंडियट्स फिल्म के वायरस से रायपुर की छात्रा को मिली प्रेरणा और आज उन्हें लोग कहते हैं लेडी वायरस

एक शब्द सीधा तो दूसरा लिखती हैं उल्टा, जिसे आईने से देखने पर वह दिखाई देता है सीधा



छत्तीसगढ़ के रायपुर की छात्रा काव्या जो दोनों हाथों से लिखने में माहिर हैं। नईदुनिया

डॉक्टर बनने का सपना

काव्या का सपना है कि वह डॉक्टर बनें। काव्या ने बताया कि पढ़-लिखकर उनकी नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने की इच्छा है। बकौल काव्या, 'जित्त लोगों को आंखों में समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं को दूर करू तकि वह भी इस सुखसुस्त दुनिया को अच्छे से देख सकें, बस यही सपना है।'

वैडमिंटन में भी है रुचि

काव्या पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी रुचि रखती हैं। बैडमिंटन उनका पसंदीदा खेल है। स्कूल का काम पूरा कर वह एक घंटा बैडमिंटन को रोजाना देती हैं। उनका कहना है कि खेल हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रखते हैं।

बंजर खेतों को आबाद कर प्रेरणा बने पौड़ी के युवा



राजीव खत्री, पौड़ी गढ़वाल

पलायन की सर्वाधिक मार से जूझ रहे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांवों को आबाद करने के लिए कंडारा क्षेत्र के युवाओं ने 'नव ज्योति और समृद्धि' समिति के बैनर तले ठोस मुहिम छेड़ दी है। सुखद यह कि इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ये युवा न सिर्फ क्षेत्र में ग्रामीणों की बंजर पड़ी भूमि को आबाद कर रहे हैं, बल्कि खेतों में कार्य करने के लिए स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं।

पौड़ी जिले में पौड़ी विकासखंड के कमेड़ा, रिठाई व टेऊठया सहित तमाम अन्य गांवों से साल-दर-साल बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। स्थानीय लोगों की मानें तो कई गांव लगभग खाली होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में पलायन रोकने और लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र के कुछ युवाओं ने अनूठी पहल की है। इसके तहत ये युवा क्षेत्र में ग्रामीणों के बंजर पड़े खेतों को आबाद कर रहे हैं। बताते हैं कि इन युवाओं ने पहले गांव से बाहर रह रहे खेत स्वामियों से बात कर उनके खेतों को आबाद करने की सहमति ली। इसके बाद एक टीम का गठन कर सभी युवाओं को

पलायन रोकने के लिए यहां के युवाओं ने शुरु की मुहिम

शुरुआत में बंजर पड़ी करीब 40 नाली भूमि को किया आबाद

इससे यहां के ग्रामीणों को भी मिल रहा है रोजगार

गांव छोड़ शहर गए युवा लौट रहे वापस



पौड़ी के कंडारा गांव में युवाओं की मेहनत ने बंजर खेतों को भी कर दिया आबाद।

अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई। नव ज्योति और समृद्धि समिति के सचिव कुलदीप गुप्ताई बताते हैं कि शुरुआती चरण में करीब 40 नाली बंजर भूमि को जोता गया है। इस पर सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेतों में कार्य करने के लिए गांव की ही महिलाओं को लगाया गया है। कुलदीप के अनुसार, खेतों के आबाद होने के बाद यदि कोई ग्रामीण अपने खेतों पर स्वयं

शहरों में रह रहे कुछ युवा भी गांव लौटकर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। निसर्णी गांव के युवा संदीप रावत दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन इस मुहिम से प्रेरित होकर अब बंजर खेतों को आबाद करने में हाथ बंटा रहे हैं। कहते हैं, 'दिल्ली जैसे महानगरों में छोटी-मोटी नौकरी करने के बजाय गांव के संसाधनों को विकसित कर अपना व्यवसाय करना ज्यादा फायदेमंद है।'

गुरुग्राम में बनेगा देश का पहला वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

प्रियंका दुवे मेहता, गुरुग्राम

साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। विहिप वेद विश्वविद्यालय में देश-विदेश के विद्यार्थी न केवल शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, बल्कि वेदों पर शोध भी कर सकेंगे। दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर सिहरौल के समीप इस विश्वविद्यालय को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए भूमि पूजन भी हो चुका है। चूंकि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में समय लगेगा, ऐसे में फिलहाल गुरुग्राम में इसे शुरू करवाने के लिए किएए के भवन को तलाशने की प्रक्रिया चल रही है।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आगामी सत्र से विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें आधुनिक वैदिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पढ़ाई होगी। विहिप वेद विश्वविद्यालय का नाम विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के नाम पर रखा जाएगा। इसका नाम वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होगा। डॉ. सुरेंद्र जैन ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को लेकर तैयारियां काफी समय से चल रही थीं। अब इसका नाम व स्थान तय कर लिया गया है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और वैदिक विज्ञान के संसाधनों से लैस होगा विश्वविद्यालय : डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऐसा स्थान तलाशना था जहां देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए सुगमता हो व वह स्थान देश के केंद्र में हो। गुरुग्राम में वह भी सिररौल बॉर्डर के नजदीक यह विश्वविद्यालय बनाने का बड़ा कारण यहां पर सभी संस्कृतियों का समावेश और एयरपोर्ट से नजदीकी है। इस विश्वविद्यालय को लेकर कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें विद्यार्थियों को आधुनिक व वैदिक विधि से शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा विवि में वैदिक टावर भी बनाया जाएगा, जहां ऑडियो-विजुअल स्टूडियो के साथ हर कक्षा में वेद और उससे जुड़ा साहित्य व पौराणिक ग्रंथ भी उपलब्ध होंगे।

विश्वविद्यालय में सुरभि सदन यानी गोशाला, मंदिर और मेडिटेशन हॉल के अलावा यशशाला भी होगी। यहां पर पौराणिक शैली में पढ़ाई करवाने के लिए ओपन एयर कक्षाएं भी लगाए जाने की तैयारियां हैं। इस विश्वविद्यालय में शुरुआत में कृषि तंत्रम, वास्तु तंत्रम, पर्यावरण

पीजीआइ ने खोजी गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की वजह

कुमार संजय, लखनऊ

गर्भावस्था के दौरान क्रॉनिक हाइपरटेंशन के जटिल कारणों का पता लगाने में संजय गांधी पीजीआइ के मैटर्नल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विभाग के विशेषज्ञों ने कामयाबी हासिल की है। इसके लिए 4,635 गर्भवती महिलाओं पर शोध किया जो हाई रिसक प्रेग्नेसी के साथ आईथी। इनमें से 7.6 फीसद में प्रीक्लेम्सिया (उच्च रक्तचाप) की परेशानी थी, जबकि 1.4 फीसद क्रॉनिक हाइपरटेंशन की शिकार पाई गई। उच्च रक्तचाप का कारण पता करने के लिए कई तरह की जांचें की गईं। उसमें पता चला कि पीडिट महिलाओं में 45 फीसद क्रॉनिक किडनी डिजीज, 30 फीसद टाकायासु अर्थराइटिस, 15 फीसद में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अलावा फीयोक्रोमोसाइटोमा सहित अन्य परेशानियां थी। विभाग की प्रो. संगीता यादव, प्रो. नीता सिंह, डॉ. श्रुति जैन और प्रो. मंवाकिनी प्रधान ने 'आइडेंटिटीफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेयर कॉज ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेसी' विषय पर शोध किया। इसे इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल प्रेग्नेसी हाईपरटेंशन ने स्वीकार किया है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप बढ़ने की परेशानी की आशंका हर 12वीं गर्भवती महिला

बढ़े यात्री

केदारनाथ में यात्रियों की आमद बढ़ने से अब तक पिछले वर्ष की अपेक्षा हो चुकी दो करोड़ से अधिक की आय, मंदिर समिति को अब तक अकेले हेली कंपनियों से ही मिल चुकी छह करोड़ रुपये से अधिक की रकम

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर सिहरौल के समीप इस विवि को खोलने की प्रक्रिया हुई शुरू

जल्द शुरू होगा भवन निर्माण का कार्य, स्नातकोत्तर कक्षाओं तक की दी जाएगी शिक्षा



डॉ. सुरेंद्र जैन

जागरण

आगामी सत्र से गूंजेगी वेदों की भाषा : इस विश्वविद्यालय को तत्काल शुरू करने के लिए किएए के भवन की तलाश की जा रही है। डॉ. सुरेंद्र जैन ने बताया कि जल्द ही स्थान का चयन कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आने वाले सत्र 2020-21 से इसमें दाखिले हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस विवि का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान व वैदिक ज्ञान को एक साथ एक मंच पर लाना और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है।

विज्ञान, लिपि विज्ञान और युद्ध तंत्रम सहित कुल 20 कोर्स करवाए जाएंगे। **देश का पहला वेद विश्वविद्यालय** : देश में वेद विद्यालय तो हैं, लेकिन वेद विश्वविद्यालय एक भी नहीं है। देशभर में जुड़ेगा। विश्वविद्यालय के देश के केंद्र में स्थापित होने से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद की कठिन भाषा का सरलीकरण हो सकेगा और इसके व्यवहारिक ज्ञान की गहराई लोगों तक पहुंच सकेगी। इस वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करवाई जाएगी।

2020

तक भारत डिजिटल वीडियो पर समय बिताने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। एक अध्ययन में बताया गया है कि अभी भारतीय करीब दो घंटा रोज डिजिटल वीडियो को दिखाने में समय बिताते हैं।

कम यात्री संख्या वाली ट्रेनों में मिलेगी छूट

राहत ▶ डबल डेकर, तेजस, गतिमान, इंटरसिटी जैसी एसी चेयरकार में मिलेगी सुविधा

50 फीसद से कम सीट बुक

होने पर कम होगा 25

प्रतिशत किराया

निशांत यादव, लखनऊ

रेलवे ने डबल डेकर, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान और इंटरसिटी सहित एसी चेयरकार ट्रेनों का किराया कम भीड़ वाले सीजन में घटाने का फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड ने डिस्काउंट फेयर स्कीम लागू करने का अधिकार जोनल मुख्यालयों के प्रिंसिपल चीफ कार्मिशियल मैनेजरी (पीसीसीएम) को दिया है। ये सभी अपने यहां ऐसी ट्रेनों को चिह्नित कर 30 सितंबर से योजना लागू करेंगे।

रेलवे अभी 50 प्रतिशत से कम मांग वाली शताब्दी के किएए को कम कर रहा है, जबकि इंटरसिटी, डबल डेकर सहित अन्य ट्रेनों में ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट बनने पर खाली सीट की बुकिंग कराते समय बेसिक किएए पर 10 प्रतिशत छूट देता है। अब तक रेलवे बोर्ड को ही किएए में छूट देने का अधिकार था।

ऐसे लागू होगा नया नियम : नए आदेश के मुताबिक पिछले साल जिन महीनों में 50 प्रतिशत से कम सीट बुक हुई होंगी, इस

लंदन में बनेगी भारतीय पक्षियों के गीतों की सबसे बड़ी वीथिका

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं अंतरराष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक प्रो. दिनेश भट्ट ब्रिटेन के ब्राइशन शहर में आयोजित इंटरनेशनल बायोकारिस्टिक्स काउंसिल में प्रतिभाग कर हरिद्वार लौट आए। उन्होंने काउंसिल में न केवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता की, बल्कि लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में विजिट भी की। प्रो. भट्ट ने बताया कि इस दौरान लंदन स्थित साउंड आर्काइव लाइब्रेरी में भारतीय पक्षियों के गीतों की वीथिका (गैलरी) बनाने पर भी सहमति बनी। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रो. भट्ट ने बताया कि ससेक्स यूनिवर्सिटी में कुल 30 वेद विद्यालय हैं। ऐसे में अशोक सिंघल वेद विश्वविद्यालय लोगों को प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक, पौराणिक और वैदिक जड़ों से जोड़ेगा। विश्वविद्यालय के देश के केंद्र में स्थापित होने से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद की कठिन भाषा का सरलीकरण हो सकेगा और इसके व्यवहारिक ज्ञान की गहराई लोगों तक पहुंच सकेगी। इस वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करवाई जाएगी।

बच्चों के लिए विद्यालय में बना दी अशोक वाटिका

किशोर जोशी, नैनीताल

स्वस्थ्य मण्डित्व में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। बच्चों को बेहतर संतुलित आहार मिलेगा तो मन-मस्तिष्क में पढ़ने की ललक भी पैदा होगी। भारत सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान की शुरुआत भले ही कुछ समय पहले की हो, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल के बेतालघाट में एक शिक्षक टिकेश्वर प्रसाद 2005 से ही बच्चों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। वह सरकारी शिक्षा की बेहतरी के लिए निजी संसाधनों को झोंकने के साथ ही बच्चों के पोषण के लिए प्रतिदिन स्कूल खुलने से पहले व बंद होने के घंटों बाद तक काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से अभिभावक पब्लिक स्कूलों का मोह त्याग बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं।

बदलाव के लिए जुनून की जरूरत : शिक्षक में जज्बा व जुनून हो तो सरकारी शिक्षा की तस्वीर बदलना मुश्किल नहीं है। बेतालघाट ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय घिरोली के शिक्षक टिकेश्वर प्रसाद ने अपनी मेहनत व लगन से विद्यालय में अशोक वाटिका स्थापित की है, जिसमें हरी सब्जी पूरे साल उगाई जाती है। इसके अलावा आलू, मूली, बीन, भिंडी, ककड़ी, तोरई, करेला समेत अन्य सब्जियां उत्पादित होती हैं। वहीं से प्रतिदिन मिड डे मील



डिस्काउंट फेयर स्कीम लागू करने का अधिकार जोनल मुख्यालयों के पीसीसीएम को दिया है। **फाइल**

▶ प्रारंभ के बार महीनों तक योजना की मॉनिटरिंग करके उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजनी होगी। सभी पीसीसीएम को 30 सितंबर तक अपने यहां की 50 प्रतिशत से कम डिमांड वाली ट्रेनों को चुनना होगा।

— नीरज शर्मा, एक्जक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड

साल उन ट्रेनों में बेसिक किएए, रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पीसीसीएम डिस्काउंट स्कीम को ट्रेन के तय रूट, आरंभ से लेकर अंतिम स्टेशन तक सहित कई रूपों में प्रारंभ कर सकते हैं। यह छूट पूरे साल, कुछ महीनों, सीजन और वीकेंड में भी

दी जा सकती है। **इस स्थिति में नहीं मिलेगी सुविधा** : पहला आरक्षण चार्ट बनने पर मिलने वाला 10 प्रतिशत डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रियायती और पीटीओ के टिकट का शुल्क पूरे किएए पर लगेगा। तत्काल कोटे के टिकट पर भी रियायती किरया लागू नहीं होगा।

▶ **ब्रिटेन से इंटरनेशनल बायोकारिस्टिक्स काउंसिल में प्रतिभाग कर लौटे पक्षी वैज्ञानिक प्रो. दिनेश भट्ट ने दी जानकारी**

कहा, दुनिया में ध्वनि संग्रहों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आधुनिक तरीके संग्रहीत होंगी भारतीय पक्षियों के गीतों की ध्वनि

हिमालयी व दक्षिण हिमालयी प्रजाति के गीतों की संख्या ही नहीं, गायन कला में भी अंतर है। संस्कृति व भौगोलिक परिस्थिति का भी पक्षी गीतों की संरचना व गायन कला पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है।

महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी (साउंड आर्काइव) की क्यूरेटर एवं आइबीएस की जूनरल सेक्रेटरी डॉ. चेरिल टिप ने भारतीय पक्षियों के गीत व संवाद विज्ञान की रिकॉर्डिंग को संकलित कर रखने के लिए एक अलग सेक्शन बनाने की बात कही। इससे विश्व फलक पर दुनिया की सबसे पुरानी व ध्वनि संग्रहों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में भारतीय पक्षियों के गीतों की ध्वनियां आधुनिक तरीके संग्रहीत हो सकेंगी। यह विश्व में पक्षी व जीव विज्ञानियों और केजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के लिए उपयोगी साबित होंगी। इस प्रयास में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सहयोग करेगा।

गंगा की लहरों पर रोमांच का सफर हुआ शुरू

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश

मानसून काल में दो माह के विराम के बाद आखिरकार मंगलवार से गंगा में राफ्टिंग सत्र का आगाज हो गया। हालांकि, इस बार गंगा का जलस्तर बढ़े होने के कारण सत्र शुरू होने में 16 दिन का विलंब हुआ। पहले दिन करीब ढाई दर्जन राफ्टों में 200 से अधिक पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ लिया।

गंगा के कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में रिवर राफ्टिंग की गतिविधि बेहद लोकप्रिय है। यही वजह है कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। मानसून काल के दौरान गंगा के जलस्तर में होने वाली अतिशय वृद्धि के चलते सुरक्षा की दृष्टि से 31 जून से 31 अगस्त तक राफ्टिंग बंद रखी जाती है। एक सितंबर से राफ्टिंग के नए सत्र का आगाज होता है, मगर इस वर्ष अगस्त के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण एक सितंबर तक गंगा का जलस्तर राफ्टिंग के अनुकूल नहीं बन पाया था। नतीजा इस दिन से राफ्टिंग सत्र शुरू नहीं किया जा सका।

दो सितंबर को सरकार की ओर से गठित तकनीकी कमटी ने गंगा में राफ्ट उतारकर राफ्टिंग की संभावना तलाशी, लेकिन गंगा का जलस्तर बहुत अधिक था। लिहाजा दस दिन बाद फिर से तकनीकी जांच करने का निर्णय लिया गया। 12 सितंबर को तकनीकी कमटी

विशेष 11

इंसान जैसा सोचेगी मशीन, देगी सलाह

जागरण संवाददाता, कानपुर : मशीन इंटेलीजेंस पर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से काम चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जब मशीन न सिर्फ इंसान की तरह सोचेगी, बल्कि त्वरित निर्णय लेकर सलाह भी देगी। घर के काम करने के साथ वाहन भी दौड़ाएगी। इससे जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। मशीनों में सोचने-समझने की क्षमता विकसित करने पर भारत समेत दुनिया के कई देश शोध में जुटे हैं। यहां सुपर वॉयस लॉनिंग व अनसुपर वॉयस लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, जिनका परीक्षण चल रहा है। ये जानकारी अडआइटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंकुश शर्मा ने हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में मंगलवार को हुई कार्यशाला में दी।

एचबीटीयू व त्यागराजर इंजीनियरिंग कॉलेज मटुड़े के संयुक्त तत्वावधान में मशीन इंटेलीजेंस पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि इंसान को मशीन ठीक वैसे ही राय देगी जैसे कोई विशेषज्ञ देता है। इसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग व आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में कार्यरत देशभर के वैज्ञानिक व वरिष्ठ प्रोफेसर शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आइबीएम ने मशीन लर्निंग के तहत वाट्सअन मशीन बनाई है जो किसी लौगल एडवाइजर की तरह सलाह दे सकती है।

गंगा में बढ़े जलस्तर के कारण 16 दिन विलंब से शुरू हो पाया राफ्टिंग सत्र

▶ **गंगा में बढ़े जलस्तर के कारण 16 दिन विलंब से शुरू हो पाया राफ्टिंग सत्र**



दो माह के विराम के बाद फिर से राफ्टिंग का सत्र शुरू हो गया है।

▶ फिलहाल रोटेशन प्रणाली से राफ्टिंग का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन एक अक्टूबर के बाद रोटेशन के नियमों से ही राफ्टिंग का संचालन किया जाएगा। समिति ने पर्यटकों की सुरक्षा व सुरक्षित राफ्टिंग के लिए जो भी नियम बनाए हैं, उनका पालन किया जाएगा।

— दिनेश भट्ट, अध्यक्ष, गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति, ऋषिकेश

ने दोवार गंगा के जलस्तर की जांच की, तब भी जलस्तर करीब एक मीटर अधिक था। सो, 15 सितंबर को कमेटी फिर से जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी।

इस पर पर्यटन विभाग ने मंगलवार से राफ्टिंग शुरू करने की अनुमति जारी की। मंगलवार को भी राफ्टिंग व्यवसायियों ने विधिवत रूप से राफ्टें गंगा में उतारी। हालांकि, पितृपक्ष को देखते हुए

उन्होंने 12 सितंबर को ही विधिवत पूजा-अर्चना कर सत्र का औपचारिक शुभारंभ कर दिया था। पहले दिन करीब 30 राफ्टों में 200 से अधिक पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ लिया। हालांकि, अभी राफ्टिंग का संचालन स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन संभव है कि अक्टूबर से गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति संचालन का जिम्मा अपने हाथ में ले लेगी।

अभी जिंदा है एनकाउंटर में मारा गया बशीरा

गुरूप्रेम लहरी, बठिंडा

पंजाब पुलिस के कुछ जांबाज अधिकारियों ने करीब 26 साल पहले बंगाल में जाकर एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। कोलकाता पुलिस को बिना विश्वास में लिए एनकाउंटर करने पर पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस अपराधी को ढेर करने पर अधिकारी हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे, वह अब भी जिंदा है। पंजाब में आतंक का पर्याय रहा मानसा के गांव भाम्मे कलां निवासी बशीर मुहम्मद उर्फ बशीरा को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। यह हम नहीं, पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है। मानसा जिले के द्युगौर थाने में रखे रिकार्ड को देख दैनिक जागरण के संवाददाता के कान खड़े हो गए। दरअसल, उस सूची में एक ऐसा नाम भी था, जिसे एनकाउंटर में मार गिराने के चर्चे आम थे। नाम था बशीरा। इस बारे में पड़ताल की तो पता चला कि पुलिस को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिर सच क्या है, यह जानने के लिए पुलिस के रिकॉर्ड खंगाले और अधिकारियों से छूतछूत की। आखिर इस पड़ताल के दौरान मुलाकात हुई 1993 में मानसा में तैनात रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तत्कालीन डीएसपी सुखदेव सिंह चहल से। उन्होंने जो जानकारी दी, वह चौंका देने वाली थी।

उन्होंने बताया कि मानसा के गांव भाम्मे कलां निवासी बशीर मुहम्मद पुत्र अली मुहम्मद (33) प्रदेश में आतंक का पर्याय था। कई थानों में उसके खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास व लूट के करीब तीस केस दर्ज थे। 31 अगस्त, 1993 में अदालत ने उसे भगोड़ा करार दे दिया था। 1993 में ही उनको और सीआरपीएफ के एसपी (ऑपरेशन) खुशी राम को सूचना मिली कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए बशीर बंगाल के तिलजला इलाके के एक फ्लैट में छिप कर रह रहे हैं। उनके नेतृत्व में खुशी राम व चार कस्टेबलों की टीम तिलजला पहुंची, जहां उन्होंने बशीर मुहम्मद को मार गिराया, लेकिन उन्होंने गलती यह कर दी कि कोलकाता पुलिस को उसके वहां छिपे होने की सूचना नहीं दी। इसके चलते कोलकाता पुलिस ने उनको व अन्य मुलाजिमों पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। सभी मुलाजिमों को उम्रकैद हो गई,लेकिन

तहकीकात

- एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दावा- 26 साल पहले कर दिया था ढेर
- बंगाल में हत्या के जुर्म में पंजाब पुलिस के अधिकारी गए थे जेल
- पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मारा गया अपराधी अब भी भगोड़ा



बशीर मुहम्मद उर्फ बशीरा की फाइल फोटो।

दूधिया वन कर पहुंचे थे बशीरा तक : बशीरा की तलाश में तत्कालीन डीएसपी सुखदेव सिंह व सीआरपीएफ के एसपी खुशी राम दूधिया बने थे। यही वजह रही कि उसको उनके बारे में भनक तक नहीं लगी। जब वह दूधिया बने पुलिसवालों से दूध ले रहा था तभी फायरिंग कर दी गई।

मेरे ध्यान में है कि बशीर मुहम्मद को एनकाउंटर 1993 में हो गया था, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में यह भगोड़ा क्यों है इसके बारे में पड़ताल कराएंगे। इसके बाद पुलिस रिकॉर्डों को अपडेट किया जाएगा।

— अरुण कुमार मित्तल, आइजी बठिंडा रंज

पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हस्तक्षेप के बाद उनको एक साल बाद रिहा कर दिया गया। इतना सबकुछ होने के बाद भी पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में बशीरा अब भी जिंदा है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब किसी भी पुलिसवाले के पास नहीं है। हां, पुलिस अधिकारी यह तो मानते हैं कि बशीरा का एनकाउंटर हो गया था, मगर उनको यह जानकारी नहीं है कि बावजूद इसके वह भगोड़ा कैसे है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि वे इस बारे में पड़ताल कराएंगे।

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>	सेंसेक्स 36,481.09 <div>642.22</div>	निफ्टी 10,817.60 <div>185.90</div>	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> सोना <div>प्रति दस ग्राम</div> ₹ 38,905 <div>₹ 150</div>	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> चांदी <div>प्रति किलोग्राम</div> ₹ 48,318 <div>₹ 290</div>	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> डॉलर <div></div> ₹ 71.78 <div>₹ 18</div>	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> कूड (बेट) <div>प्रति बैरल</div> \$ 67.97
---	---	---	---	---	---	---

सीजी पावर के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर पर प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रे्ट : सेबी ने सीजी पावर के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और कंपनी से जुड़े तीन अन्य लोगों पर पुजी बाजार में किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें गौतम थापर के अलावा कंपनी के पूर्व सीएफओ वीआर वैकटेश, पूर्व डायरेक्टर माधव आचार्य और बी. हरिहरन का नाम शामिल है। सेबी ने यह कदम मीडिया में आई न्यूज रिपोर्टों को आधार बनाकर उठाया है।

6 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा बाजार है। एपल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भारत में उत्पादन इकाई लगाने जा रही हैं। इससे आने वाले दिनों में व्यापक असर दिखेगा।
— रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

होटल और आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी की दर घटाने की तैयारी

आसार ▶ 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसले की उम्मीद

ऑटोमोबाइल और बिस्कुट उद्योग की उम्मीदों को लग सकता है झटका

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल होटलों पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट की जा सकती है। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 18 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से प्रोत्साहन पैसेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की 37वाँ बैठक के लिए जीएसटी गेट से संबंधित जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें 400 से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है, लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट कमेट्री ने की है। फिटमेंट कमेट्री में केंद्र और



फिटमेंट कमेट्री ने होटलों पर जीएसटी घटाने के दो विकल्प सुझाए हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी की दरें यही कमेट्री निर्धारित करती है। कमेट्री ने होटलों पर जीएसटी घटाने के दो विकल्प सुझाए हैं। पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये से ज्यादा टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी की दर 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करने की सिफारिश की है। दूसरे विकल्प के तहत 7500 रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 करने की सिफारिश की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 परसेंट या इससे कम जीएसटी के दायरे में आ सकें।

सूत्रों ने कहा कि कमेट्री ने रेस्तरां की तर्ज

पर आउटडोर कैटरिंग के लिए जीएसटी की दर 18 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) करने की सिफारिश की है। इसी तरह माचिस, कप व प्लेट्स पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश की है। सूत्रों ने कहा कि काउंसिल ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी की दरें कम करने से परहेज कर सकती है। ऑटो सेक्टर कारों की बिक्री में गिरावट का हवाला देते हुए जीएसटी दर घटाने की मांग कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट कमेट्री ने अपना मत की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 परसेंट करने से सरकार के खजाने पर सालाना 50 से 60 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है।

होटलों पर जीएसटी की दर कम होने से पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा

भारत में यह है होटलों पर जीएसटी की दर	
होटल टैरिफ	जीएसटी दर (परसेंट में)
1000 रुपये से कम	शून्य
1000 से 2500 रुपये	12
2500 से 7500 रुपये	18
7500 रुपये से अधिक	28

इसी तरह काउंसिल बिस्कुट उद्योग की जीएसटी कम करने की मांग को भी खारिज कर सकती है। गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों को भारत के होटलों में ठहरने के लिए काफी अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में होटलों पर टैक्स की दर अपेक्षाकृत कम है। इसके चलते बहुत से पर्यटक दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था। माना जा रहा है कि काउंसिल का कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।

प्लास्टिक बोतलों पर उद्योग क्षेत्र ने सरकार को भेजा सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने के मुद्दे पर इससे जुड़े उद्योगों ने सरकार को अपने सुझाव भेज दिए हैं। इनमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक तैयार करने और अन्य वैकल्पिक वस्तुओं के लिए रिसर्च पर जोर दिया गया है। उद्योग क्षेत्र के इन सुझावों के आधार पर सरकार फैसला ले सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इन सुझावों पर सरकार विचार करेगी। इन्हें संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया गया है।

पासवान ने बताया कि नौ सितंबर को यहां पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। उनसे लंबी चर्चा के बाद सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपनी राय लिखित रूप में भेजने को कहा गया था। सुझावों में सबसे ज्यादा जोर जैविक प्लास्टिक बनाने पर है। उनका कहना है कॉर्न से तैयार होने वाला यह प्लास्टिक मिट्टी के साथ सड़ जाता है। यह किसी भी तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता।

अपने अन्य सुझावों में उद्योग क्षेत्र ने मौजूदा प्लास्टिक बोतलों के रिसाइलिंग का सुझाव दिया है। काराज के साथ कंपोस्टेबल (मिट्टी में सड़ जाने वाले) प्लास्टिक के उपयोग पर जोर दिया गया है, जो इकोफ्रेंडली होगा। पीने के पानी की पैकिंग में काराज के उपयोग के लिए और रिसर्च पर ब्यव करने की जरूरत है। इसके अलावा पीने के पानी के डिस्पेंसर जगह-जगह लगाए जाएं। पेयजल के लिए कांच की बोतलों का उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक की पैकिंग पर जोर दिया जाए और इसके लिए एफएसएसएआइ और भारतीय मानक



प्रतीकात्मक फोटो

कंपोस्टेबल प्लास्टिक तैयार करने पर उद्योग जगत का जोर

पैकिंग के लिए वैकल्पिक वस्तुओं पर होगी रिसर्च

ब्यूरो मानक विकसित करे। जगह-जगह वाटर एटीएम लगाए जाने के भी सुझाव दिए जाएं। साथ ही पेयजल की पैकिंग को लेकर किसी और विकल्प की तलाश के लिए अनुसंधान पर पूरा जोर दिया जाए। प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए देश में सघन जागरूकता अभियान चलाने की सख्त जरूरत बताई गई है। सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों व विभागों में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी जाए, जो आम लोगों के लिए उदाहरण बन सके।

कंपनियों की ओर से दिए गए सुझाव सभी संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं, जो इन पर विचार कर अपनी अंतिम सिफारिश सरकार को सौंपेंगे। पेट्रो केमिकल विभाग जहां एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की परिभाषा तैयार कर रहा है, वहीं पर्यावरण मंत्रालय की समिति इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार कर रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इन सारे सुझावों को साझा कर संयुक्त और फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखेगी।

कच्चे तेल की मार से औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार

मुंबई, प्रे्ट : पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के दबाव में भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। बीते सत्र में भी इनमें गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान ऑटो सेक्टर और वॉकिंग कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 642.22 अंक यानी 1.73 परसेंट की गिरावट के साथ 36,481.09 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 185.90 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह 1.69 परसेंट गिरकर 10,817.60 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय सेंसेक्स 704 अंकों तक लुढ़क गया था। सोमवार को सेंसेक्स में 262 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी।

मंगलवार को सेंसेक्स में सबसे ज्यादा नुकसान ह्रीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, मारुति और एस्सोआइ को हुआ। इन कंपनियों के शेयर 6.19 परसेंट तक गिर गए। वहीं एचयूएल, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमत में 20 परसेंट तक उछाल के बाद



प्रतीकात्मक फोटो

अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा ईरान पर हमले के डर से निवेशक सहमे

कच्चे तेल की कीमत मामूली सुघरकर 67.97 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची

मंगलवार को इसमें कुछ नरमी आई। इस दौरान यह 67.97 बैरल प्रति डॉलर पर रहा। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का असर रुपये पर भी देखा गया। दिन के कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 71.78 के स्तर पर चल रहा गया।

सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले के

देश में आर्थिक मंदी नहीं, सुस्ती है : कैट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कारोबारी संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि देश में आर्थिक मंदी नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में सुस्ती है। इसका कारण बाजार में नकदी के प्रवाह में कमी आना है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के हालिया इंतजामों से यह सुस्ती भी जल्द दूर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक कंपनी की लांच एसयूवी की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। हालात यह हो गए कि कंपनी को बुकिंग लेना बंद करना पड़ा है।

जहां तक ऑटो सेक्टर में सुस्ती की बात है तो इसके कई कारण हैं। जिनमें एक कारण अगले साल से वीएस-6 की अनिवार्यता भी शामिल है, जिसके कारण लोग गाड़ियां खरीदने की योजना को अगले साल के लिए टाल रहे हैं। खंडेलवाल ने कहा कि खुदरा बाजार स्तर पर सुस्ती पर है। इसे पूरे भारत में महसूस किया जा रहा है। अधिकांश नकदी रिटल एंटरटे सेक्टर व सोने के निवेश में फंसी हुई है।

किसानों के खाते में जाए फसल ऋण पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रिजर्व बैंक के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर ब्याज सब्सिडी का भुगतान बैंकों को करने के बजाय सीधे किसानों के खाते में करने को कहा है। इस सिफारिश से कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो सकेगी।

रिजर्व बैंक के इस ग्रुप का कहना है कि इंटरैस्ट सबवेंशन स्कीम की जगह धनराशि लक्षित लाभार्थियों को व्यक्तिगत या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डीवीटी के जरिये ट्रॉसफर करनी चाहिए। लाभार्थियों में सीमांत और छोटे किसानों, बटवाईदार, पट्टेदार और भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं। ग्रुप ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपी है। फिलहाल सरकार शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर ब्याज दर में छूट के तौर पर बैंकों को आरबीआइ और नाबाई के

दो दिन में निवेशकों ने गंवाए 2.72 लाख करोड़

शेयर बाजारों में लगातार दो दिन की गिरावट से निवेशकों के करीब 2.72 लाख करोड़ रुपये डूब गए। दो दिन हुई बिकवाली के चलते बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,72,593.54 करोड़ रुपये घटकर 1,39,70,356.22 करोड़ रुपये रह गया। सेंट्रल ब्रोकिंग के सीईओ निरवल माहेश्वरी के मुताबिक तेज की बढ़ी कीमतों के कारण चालू खाते का घाटा और राजस्व घाटा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। इससे निवेशकों में नकारात्मक संदेश गया है।

बाद पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सऊदी अरब और अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। जिसका सीधा असर भारतीय एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 70 परसेंट ऑयल आयात करता है।

सोना 150 रुपये टूटा, चांदी में 290 रुपये की गिरावट

नई दिल्ली, प्रे्ट : मंगलवार को कमजोर मांग के चलते सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में सोने की कीमत में 150 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान यह 38,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दूसरी ओर चांदी 290 रुपये के नुकसान में बोली गई। इस तरह यह 48,318 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। एचडीएफसी सिव्थुरिटीज के विश्लेषक तपन पटेल के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट सोने की मांग में कमी के चलते इसकी कीमत में 150 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को दिल्ली में सोना 39,055 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इंटरनेशनल माफिए में भी सोने में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान न्यूयॉर्क में यह 1,497 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के हिसाब से बिका। ग्लोबल मार्केट में चांदी 17.81 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से बिकी।

कसी कसर

रबी सीजन की तैयारियों पर 20 सितंबर को राजधानी में होगी चर्चा, भूमि की पर्याप्त नमी के उपयोग पर दिया जाएगा जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी रबी सीजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए वार्षिक रबी सीजन अभियान सम्मेलन इसी शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के कृषि मंत्रियों और उनके सचिव जुटेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में रबी फसलों की खेती की जरूरतों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि समय से उसे पूरा किया जा सके। सम्मेलन में खरीफ फसलों के ताजा हालात और उत्पादन के अनुमान पर भी चर्चा हो सकती है।

चालू सीजन में जबर्दस्त बारिश होने के साथ मानसून निर्धारित समय से अधिक तक सक्रिय है। इससे जमीन में पर्याप्त नमी है, जिसका सकारात्मक असर रबी सीजन की फसलों पर पड़ेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब फसलों की बोआई समय से करा दी जाए। बोआई में विलंब होने से नमी का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसी के मद्देनजर रबी सीजन-2019 अभियान सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि सभी राज्य इसे प्राथमिकता पर लें और बोआई में देववजह देर न हों।



मानसून सीजन में हुई बेहतर बारिश का लाभ उठाने के लिए सही समय पर बोआई जरूरी।

प्रतीकात्मक फोटो

रबी सीजन के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों और कृषि वैज्ञानिकों को विशेष तौर पर बुलाया गया है, जो अपने सुझाव दे सकें। राज्यों की ओर से उठाई जाने वाली तकनीकी मांगों को समय से पूरा करने पर जोर दिया

जाएगा। फर्टिलाइजर, बीज और कीटनाशकों की मांग को लेकर राज्य ज्यादा ही संवेदनशील रहते हैं। इसके लिए संबंधित केमिकल व फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ बीज निगम के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे।

दरअसल, रबी सीजन की बड़ी फसलों में गेहूं प्रमुख है। इसी तरह दलहन में चना और तिलहन में सरसों को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। तिलहन और दलहन की खेती ज्यादातर अर्धवर्षित क्षेत्रों में होती है। इस बार भूमि की पर्याप्त नमी का फायदा इन फसलों को मिल सकता है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से संयुक्त सचिव (बीज) अपनी प्रस्तुति देंगे। जिला स्तर पर किसानों को तकनीकी जानकारी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले केवीके की भूमिका पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के उप महानिदेशक डॉक्टर एके सिंह प्रस्तुति देंगे।

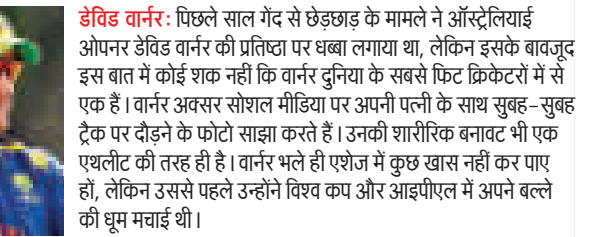
टैक्सो एग्रीगेटर्स की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वदेशी जागरण मंच ने उबर, ओला जैसी केब एग्रीगेटर्स की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की है। मंच ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में शिकायत की है। गडकरी को लिखे पत्र में मंच के अखिल भारतीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कदम रखा था। अब सर्ज प्राइसिंग के नाम पर इन कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। पिछले दिनों मुंबई में एक ग्राहक से छह मिनट के ड्राइव के लिए 2000 रुपये का भाड़ा वसूला गया। मंच ने मांग की है कि सर्ज प्राइसिंग के तहत 25 फीसद से अधिक किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एडवांस बुकिंग में सर्ज प्राइसिंग की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेटर कंपनी या ड्राइवर की ओर से राइड कैसिल किए जाने पर दंडस्वरूप 100 रुपये या

सर्ज प्राइसिंग के नाम पर कई गुना किराया वसूल रही है ओला, उबर जैसी कंपनियां

किराए के 20 फीसद के बराबर रकम ग्राहक के खाते में ट्रॉसफर होनी चाहिए। अभी एग्रीगेटर ग्राहक से तो जुर्माना वसूल लेते हैं, पर खुद नहीं भरते। लिहाजा उनके लिए बुनियादी ग्राहक सेवा के मानक बनाए जाने चाहिए ताकि जरूरत पर विचार कर रहा है। 2016 के दिशाचिदेशों में भी इसकी अनुमति दी गई है। इसलिए मंत्रालय को मोटर एक्ट के तहत जनहित में एग्रीगेटर्स के लिए नियम अधिसूचित करने चाहिए। अन्यथा राज्य अपने हिसाब से नियम बना लेंगे।



डेविड वार्नर: पिछले साल गैर से छेड़छाड़ के मामले ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर की प्रेक्टिशा पर धब्बा लगाया था, लेकिन इसके बावजूद इस बात को ठीक शक नहीं कि वार्नर दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर में से एक हैं। वार्नर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ सुबह-सुबह ट्रैक पर दौड़ने के फोटो साझा करते हैं। उनकी शारीरिक बनावट भी एक एथलीट की तरह ही है। वार्नर भले ही एशेज में कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन उससे पहले उन्होंने विश्व कप और आइपीएल में अपने बल्ले की धूम मचाई थी।

